सूर्योदय 5:33 सूर्यास्त 7:22

आज का तापमान

शिमला	16.8 न्यू	21.2 अधि
धर्मशाला	21.6 न्यू	27.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,391
निफ्टी	23,869

सोना 1,45,000 चांदी 2,22,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 9 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 90, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच युवाओं के हित में आया बड़ा बयान

पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए बनाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीरवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं, इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'शिक्षा तंत्र की तबाही' छिपाने की कोशिश करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में आरोप लगाया कि देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं।

रिजिजू बोले- नीट पेपर लीक पर सरकार किसी भी तरीके से चर्चा को तैयार

लोकसभा की कार्यवाही वीरवार को हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा- सरकार लोकसभा और राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर विपक्ष जिस तरीके से, जिस तारीख को और जितनी देर चाहे, चर्चा के लिए तैयार है।

संसद के बाहर एनडीए-विपक्षी गठबंधन आमने-सामने, प्रियंका नारे लगाते एनडीए सांसदों के पास पहुंचीं

एजेंसी, नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन वीरवार को संसद भवन के बाहर एनडीए व विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध-प्रदर्शन में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं, इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिलकुल करीब चली गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई, तो भारी हंगामा शुरू हो गया। इस पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 3 बजे तक स्थगित कर दी गई, जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो सांसदों ने फिर से हंगामा कर दिया। इसके बाद राज्यसभा भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सरकार बोली- सीजेपी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया

कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकराई ऑफर, कहा- बात करनी है, तो सरकार आए जंतर-मंतर

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार ने वीरवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा जा चुका है। हालांकि, सीजेपी ने कहा है कि सरकार को बात करनी है, तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे। हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है।

20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में 28 जून से शामिल हुए सोनम वांगचुक अनशन पर हैं और फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं।

सीजेपी प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई आज

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में अपील की गई है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को बंधक बना दिया है। कई सड़कें बंद हैं व आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि ठीक है, कल सुनवाई होगी। वकील बरुण कुमार सिन्हा ने यह याचिका दाखिल की थी।

सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन

20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन की अपील की है। संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कहा कि सभी जिलों में एक दिन का प्रदर्शन कर पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई जाए।

अन्ना हजारे तबीयत खराब होने के कारण मौन प्रदर्शन से उठे

अन्ना हजारे ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर मौन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान अन्ना हजारे भावुक भी हो गए। फिर तबीयत खराब होने के कारण कुछ देर बाद उन्हें प्रदर्शन स्थल से जाना पड़ा। उनके जाने के बाद भी मौन प्रदर्शन जारी रहा।

न्यूज शॉर्ट्स

वैभव बने टी-20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन

एजेंसी, हरारे। जिम्बाब्वे ने पहले टी-20 में भारत को 126 रन का टारगेट दिया है। हरारे में टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में भारत ने 10 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी 50 और अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे टी-20 इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा। वेस्ली मधेवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन की पारी खेली। आखिर में तदिवानाशे मरुमानी ने नाबाद 27 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया। भारत की ओर से मयंक यादव व प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। मयंक ने पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट किया और फिर डियोन मायर्स का विकेट भी झटका। शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला। वेस्ली मधेवेरे रन आउट हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द की

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम ने खुद सरेंडर किया था। सोनम को खुद पता था कि उसकी तलाश किस गुनाह में है। उन्होंने कहा था कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। उसके भाई को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में हुई गलती टाइपिंग की गलती थी।

अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

एजेंसी, अमृतसर। कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह अत्याधुनिक पिस्तौल, एक किलोग्राम हेरोइन, एक किलोग्राम अफीम और नशा तस्करी से जुड़े 10 हजार रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। वहीं, हैंडलर अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए अवैध हथियार और मादक पदार्थों की खेप भारत भेजता था। आरोपियों का काम इन हथियारों और नशीले पदार्थों को आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाना था।

इस मामले में थाना छेहरटा और थाना कैंटोनमेंट में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों की जांच कर रही है, ताकि विदेश में बैठे हैंडलरों से जुड़े सभी सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।

पंखा रोड की बदलेगी सूरत : मुख्यमंत्री रेखा

ढका जाएगा नाला; स्वच्छता के लिए दिए 2300 करोड़ रुपए

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से पंखा रोड की दुर्गति हम सभी ने देखी है। यह पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन कूड़े के कारण यहां का हाल बुरा था। पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व विधायक ने इस समस्या की पूरी अनदेखी की, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पर्याप्त फंड देकर दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाने का प्रबंध किया। किसी बजी शहर की सुंदरता स्वच्छता से आंकी जाती है।

उन्होंने कहा कि पहले पार्षदों का रोना रहता था, टिप्पर नहीं है, फंड नहीं है, अब सब कुछ बदलने वाला है। पूरी दिल्ली में बदलने वाला है। पर्याप्त संसाधन दिए जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने

◆ सीएम ने कहा- जो देश का अहित करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा

निगम को 2300 करोड़ अतिरिक्त बजट दिया ताकि स्वच्छता में आधुनिकता आए।

मैकेनिकल संसाधन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आप देखिए कूड़ा घर भी सुंदर नजर आ है। रोजाना 14 हजार मीट्रिक टन कूड़ा, इसमें 6 हजार ही प्रोसेस होता था, इसे खत्म करने के लिए पहाड़ों पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग मशीन लगाई गई। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समय समय पर स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, जिस दिन 15 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले वेस्ट एनर्जी प्लांट लग जाएंगे उस दिन पहाड़ खड़े होने बंद हो जाएंगे। इस पर काम हो रहा है।

सीएम ने कहा कि जो देश का अहित करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पंखा रोड का सेंट्रल व्रज भी बेहतर हो। लोगों की मांग है कि पंखा रोड नाला ढका जाए। मुख्यमंत्री बोली बना देंगे, विरासत में मिली समस्याओं का समाधान हो रहा है। क्या इससे पहले आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा कि वह कूड़े की समस्या का जायजा ले रही।

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम फास्ट ट्रैक कोर्ट : सीएम धामी

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है।

उन्होंने स्वागत करते हुए इसे युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार पहले ही राज्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महिला कर्मचारी से एयरलाइन कंपनी की कैब में दुष्कर्म

एजेंसी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 37 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक ड्यूटी पर जा रही प्राइवेट एयरलाइन की महिला केबिन क्रू मेंबर के साथ उसकी ऑफिशियल कैब के ड्राइवर ने रास्ते में दुष्कर्म किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, महिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। पुलिस ने 23 साल के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के तुरंत बाद पीड़िता राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं (जैसे दुष्कर्म और हमले की धाराओं) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।

श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

एजेंसी, कोलंबो। श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी एक नौका भी जब्त कर ली गई। श्रीलंका की नौसेना ने यह जानकारी दी।

नौसेना ने कहा कि ये मछुआरे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार कर तलैमन्नार के उत्तर में स्थित श्रीलंका के जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों के मुद्दे को लेकर जारी तनाव के बीच ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यह मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव का लंबे समय से कारण रहा है। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान में कहा कि बुधवार शाम चलाए गए अभियान के दौरान नौ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। नौसेना के अनुसार, मछली पकड़ने वाली 50 से अधिक भारतीय

नौकाओं ने ईरानातीवु के दक्षिण में श्रीलंका के जलक्षेत्र में कथित तौर से अवैध रूप से प्रवेश किया और वहां गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ी जा रही थीं। श्रीलंका की नौसेना ने जारी एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए नौ भारतीय मछुआरों और जब्त की गई उनकी नौका को कानूनी कार्रवाई के लिए मन्नार के मत्स्य निरीक्षक के हवाले कर दिया गया। इस वर्ष 15 अप्रैल तक कोलंबो के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नौसेना 128 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर चुकी थी और 18 नौकाएं जब्त कर चुकी थी।

लश्कर के 2 आतंकियों के घर आईडी लगाकर ढहाए

एजेंसी, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रशासन ने वीरवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के घर आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई लाल चौक में पुलिस बल के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के एक दिन बाद की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जिन आतंकियों के मकान गिराए गए, उनमें बिजबेहड़ा के गुरी गांव निवासी आदिल ठोकर और हसनपोरा निवासी हारून गनई शामिल है। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कॉन्स्टेबल कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में ये दोनों आतंकी भी शामिल थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग स्थित लाल चौक पर आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया था। भारतीय रिजर्व पुलिस और एसओजी से जुड़े हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे।

हिमाचल में लागू होगी सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति

एक करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं में अनिवार्य होगा सुरक्षा ऑडिट

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की कमी दर्ज होने के बावजूद सरकार ने सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। नीति के तहत सड़क सुरक्षा को सड़क निर्माण की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन व रखरखाव का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल में दुर्गम भू-भाग, तीखे मोड़ और मौसम की चुनौतियों को देखते हुए सड़क सुरक्षा ऑडिट को महत्वपूर्ण माना गया है। नई नीति के अनुसार सड़क परियोजनाओं के पांच चरणों में ऑडिट किया जाएगा। इसमें

◆ सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही सरकार: सीएम सुक्खू

प्रारंभिक डिजाइन, डीपीआर चरण, निर्माण चरण, सड़क खोलने से पहले निरीक्षण और पहले से निर्मित सड़कों का समय-समय पर ऑडिट शामिल है। ऑडिट भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप प्रमाणित रोड सेफ्टी ऑडिटर या निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में रोड सेफ्टी सेल स्थापित किया जाएगा, जो ऑडिट कार्यक्रम की निगरानी, ऑडिटरों का पैनल तैयार करने, अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

एक करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क परियोजनाओं में ऑडिट के लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ सड़क नेटवर्क तैयार करना है, जिसमें मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा ऑडिट से दुर्घटनाओं के संभावित कारणों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में प्रदेश में 2,253 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो वर्ष 2024 में घटकर 2,107 रह गईं। इसी अवधि में दुर्घटनाओं में मृत्यु संख्या 892 से घटकर 806 और घायलों की संख्या 3,449 से घटकर 3,290 हो गई।

नीट विवाद: सीएम सैनी बोले- युवाओं को भड़काने का काम कर रहा विपक्ष

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दौरे के दौरान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) सिरसा के ऑडिटोरियम हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति (ग्रीवेंस) की मीटिंग में बिजली निगम के एक जेई और रानियां थाना के एएसआई को चार्जशीट करने के आदेश दिए।

एक मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए। 18 शिकायतों पर सुनवाई हुई। नीट को लेकर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज के सवाल पर सीएम नायब सैनी ने मीडिया को दिए बयान में कहा, हरियाणा में सैट हुआ, जिसमें एक बच्चा, माता-पिता ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे यहां नीट का पेपर हुआ, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई। विपक्ष ने जो तांडव खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी

◆ सिरसा में सीएम की ग्रीवेंस मीटिंग, जेई व एएसआई को चार्जशीट करने के आदेश

हो या इंडिया गठबंधन के ईर्द-गिर्द के लोग हो। युवाओं को भड़काने, झूठ बोलकर उनको बरगलाने का काम किया है। ये विपक्ष किया है व सरकार गंभीरता से युवाओं के साथ काम कर रही है। अगर कहीं इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और उस इंडिया गठबंधन को अपने गिरेबां के अंदर झांककर देखना चाहिए। उनके समय में युवाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था, कितने पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही विजन है युवाओं को सशक्त व मजबूत करना। युवाओं में विश्वास बहाली करना। ये विश्वास बहाली करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। कांग्रेस ने युवाओं का विश्वास तोड़ा था और कांग्रेस के समर्थित लोग है, दल है, उन्होंने विश्वास तोड़ा था।

जनता दर्शन गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश

गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार करेगी भरपूर मदद : योगी

एजेंसी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित, पारदर्शी तथा संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है व किसी भी स्तर पर जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वीरवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी से आत्मीयता के साथ संवाद किया। उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित

अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पहुंचे, जिन्होंने गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी भी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र मरीजों के इलाज का विस्तृत इस्टीमेट तत्काल तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि सरकार जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी तेज की जाए, ताकि उन्हें भविष्य में भी बेहतर और निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उसकी समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से राजस्व एवं पुलिस विभाग से जुड़े मामलों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। पारिवारिक विवादों के मामलों में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले संवाद और आपसी सहमति से समाधान का प्रयास किया जाए। यदि आवश्यक हो तभी विधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता लोगों को राहत पहुंचाना है। इसलिए हर शिकायत का निस्तारण तत्परता, पारदर्शिता और मानवीय संवेदनाओं के साथ किया जाना चाहिए।

गोशाला पहुंचकर की गोसेवा, गोवंश को खिलाया गुड़

जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरा के अनुरूप रही। उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया। अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला पहुंचे। गायों और अन्य गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने गोशाला के कार्यकर्ताओं से गोवंश के स्वास्थ्य, चारे और देखभाल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उनके बेहतर संरक्षण और सेवा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। गोशाला में मुख्यमंत्री का स्नेहपूर्ण व्यवहार और गोसेवा का दृश्य वहां उपस्थित लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

न्यूज ब्रीफ

शिमला में एलआईसी का कैंपस इंटरव्यू 25 को

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी प्रवीण नगराईक ने बताया कि एलआईसी ऑफ इंडिया, शाखा संजौली द्वारा 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे शर्मा डेस्टिनेशन आहार विला, मशोबरा-2 में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती अभियान में महिला करियर एजेंट और रूरल करियर एजेंट के कुल 100 पद भरे जाएंगे। महिला करियर एजेंट के 50 पदों के लिए 10वीं पास महिला अभ्यर्थी, जबकि रूरल करियर एजेंट के 50 पदों के लिए 10वीं पास पुरुष व महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानदेय के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों सहित साक्षात्कार में शामिल हों।

चंद्रशेखर व लोकमान्य तिलक की जयंती मनाई

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जुखाला में अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद व राष्ट्रनायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनिदेशक शिक्षा व गुणवत्ता निशा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थान के प्रधानाचार्य राकेश मनकोटिया ने प्रशिक्षणार्थियों से भारतीय संस्कृति के संरक्षण, साहित्य से जुड़ने और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रवक्ता राकेश ठाकुर ने लोकमान्य तिलक के स्वराज के सिद्धांतों और चंद्रशेखर आजाद के साहस व बलिदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने भारतीय संस्कृति, नारी सशक्तिकरण, नशा निवारण व सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर विचार रखे। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रिया शर्मा को सम्मानित किया गया।

डुकली पहुंचे बंबर ठाकुर, सड़क निर्माण का दिया भरोसा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र की रघुनाथपुरा पंचायत के डुकली गांव में वीरवार को पूर्व विधायक एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंबर ठाकुर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और क्षेत्र के विकास को लेकर आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क सुविधा की मांग उठाई। इस पर बंबर ठाकुर ने कहा कि डुकली गांव के लिए प्राथमिक सड़क निर्माण कार्य अपनी निजी आय से शुरू करवाएंगे, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद इसके विस्तार और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि डुकली गांव के समग्र विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक 6 को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी राहुल कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक 6 अगस्त को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे। डीसी ने समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्यों से आग्रह किया है कि यदि वे किसी विषय को बैठक में चर्चा के लिए शामिल करवाना चाहते हैं तो अधिकतम दो मदों के प्रस्ताव 30 जुलाई, 2026 को शाम 4 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर बैठक में उपस्थित रहने का भी आग्रह किया है।

भाजपा सरकार में नीलाम हुए भर्ती पेपर लाखों युवाओं के साथ हुआ धोखा : कांग्रेस

कहा- वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल तथा कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती पेपरों की मंडी सजी हुई थी और उस मंडी में पेपर खुलेआम नीलाम होते थे, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोए रहे।

उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ व हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग में खुलेआम भर्ती पेपरों की नीलामी होती रही, लेकिन एक भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और अपने चहेतों को नौकरियां बांटी। धनी राम शांडिल और चंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई व उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता व ईमानदारी में विश्वास रखती है तथा मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग को भंग कर उसके स्थान पर राज्य चयन आयोग का गठन किया।

उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हिमाचल के संदर्भ में पेपर लीक का मुद्दा उठाना भाजपा सरकार के पापों की याद दिलाता है, क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के विपरीत बयान देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के सारे रिकॉर्ड टूटे और बेरोजगार युवाओं के साथ छल हुआ।

पेपर लीक मामलों पर केंद्र जवाबदेही तय करे

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। हाल ही में नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने भी देशभर के करोड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता पैदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करनी चाहिए। युवाओं पर बल प्रयोग की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे युवाओं की आवाज को केंद्र सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। इसी कारण उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शन में शामिल लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

लोकतंत्र नहीं, अराजकता की राजनीति कर रही है कांग्रेस : डॉ. राजीव बिंदल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा से भागने वाली कांग्रेस अब सड़क पर अराजकता फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करना, भाजपा मुख्यालय का घेराव करना और हिंसक माहौल बनाना लोकतंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का प्रयास है। डॉ. बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।' भाजपा भी इसी संकल्प के साथ देश के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. बिंदल ने कहा कि पेपर लीक सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच करवाई, दोषियों को गिरफ्तार किया, पुनः परीक्षा आयोजित कराई, परीक्षा प्रणाली में व्यापक तकनीकी सुधार किए और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून का शिकंजा और अधिक कड़ा होगा।

कोचिंग के अभ्यर्थियों को मुफ्त आवास उपलब्ध करवाएंगे विक्रम

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रथम पुलिस सशस्त्र वाहिनी जुन्गा में 27 जुलाई से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती की निशुल्क कोचिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने निशुल्क आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

मीडिया को जारी बयान में खुश विक्रम सेन ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक प्रतिभाशाली युवा आर्थिक तंगी के कारण निजी संस्थानों में कोचिंग नहीं ले पाते। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई यह निशुल्क कोचिंग योजना विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और सभी के लिए पुंलिस बटालियन में पर्याप्त आवास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ऐसे में वह पुलिस विभाग को हरसंभव सहयोग देंगे, ताकि सभी अभ्यर्थियों को रहने की बेहतर सुविधा मिल सके और अच्छे वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को संवार सकें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और सरकार को इस दिशा में ऐसे सार्थक प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए। प्रथम पुलिस सशस्त्र वाहिनी जुन्गा के कमांडेंट भूपेंद्र नेगी ने युवाओं के लिए निशुल्क आवास उपलब्ध कराने की घोषणा पर जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कोचिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 590 से बढ़कर 615 हो गई है, जिनमें 414 पुरुष तथा 201 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं।

अरबी के पत्ते से बने पतीड़ हर रसोई की स्पेशल डिश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम आते ही रसोई में पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन्हीं व्यंजनों में अरबी के पत्तों से बनने वाले पतीड़ (धीधड़े) का विशेष स्थान है।

स्वाद, पौष्टिकता व लोक परंपरा का अनूठा संगम माने जाने वाले पतीड़ आज भी पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान बने हुए हैं। शिमला जिले के क्योंथल क्षेत्र सहित सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में बरसात के दिनों में अरबी के कोमल पत्तों से पतीड़ और पकौड़े बनाने की परंपरा आज भी जीवित है। स्थानीय भाषा में इन्हें धीधड़े कहा जाता है। देसी घी या दही के साथ परोसे जाने वाले इन व्यंजनों का स्वाद लोगों को बरसात का बेसब्री से इंतजार करवाता है। पतीड़ केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा हैं। डगैली (डगवांस) पर्व के अवसर पर क्योंथल, सिरमौर और सोलन क्षेत्रों में पतीड़ बनाने की विशेष परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार रात्रि में घर की दहलीज पर पतीड़ रखकर धारदार औजार से काटकर उन्हें डायनों को अर्पित किया जाता है। यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है और स्थानीय लोक विश्वासों का प्रतीक मानी जाती है। जुन्गा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक दयाराम वर्मा, जबर सिंह ठाकुर, प्रीतम सिंह ठाकुर और योगमाया शर्मा बताते हैं कि पहले के समय में जब अनाज की कमी होती थी, तब लोग अरबी के पत्तों से पतीड़ बनाकर अपना गुजारा करते थे। सामूहिक श्रम (बुआरा) और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी बड़े आकार के अरबी के पत्तों पर भोजन परोसने की परंपरा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अरबी के पत्ते केवल भोजन का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आयुर्वेद में अरबी के पत्तों को गुणों की खान माना गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. विश्वबंधु जोशी के अनुसार स्थानीय भाषा में श्लांबूश् कहलाने वाले इन हृदयाकार पत्तों में विटामिन-ए, विटामिन-सी, आयरन, फोलेट, कैल्शियम तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उचित विधि से पकाने पर ये पत्ते शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

परंपरा को सहेजने की जरूरत

आधुनिक खान-पान के बढ़ते प्रभाव के बीच पतीड़ जैसी पारंपरिक पहाड़ी डिश आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यह केवल स्वाद का नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं और प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतीक है। नई पीढ़ी तक इस विरासत को पहुंचाना समय की आवश्यकता है, ताकि आने वाले वर्षों में भी बरसात का मौसम पतीड़ की खुशबू और पहाड़ी संस्कृति की मिठास से महकता रहे।

बिलासपुर में बरसात से 20 करोड़ का नुकसान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी राहुल कुमार ने बताया कि जिले में भारी बरसात के कारण अब तक करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 19.05 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 66 लाख रुपए, शिक्षा विभाग को 30 लाख रुपए और बिजली बोर्ड को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान शामिल है। उन्होंने बताया कि बरसात से प्रभावित एक सड़क अभी बंद है, जिसे जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पेयजल योजनाओं की बहाली के लिए भी विभागों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। उपायुक्त ने लोगों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने सर्पदंश और नदी-नालों में डूबने की घटनाओं को देखते हुए सावधानी बरतने का आह्वान किया। आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।

भाजपा अपनी नाकामियों, विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही : विनय

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय पेपर लीक हुए, हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर तक बेचे गए थे।

विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है, जिसमें नड्डा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक हुए हैं। विनय कुमार ने कहा है कि भाजपा अपनी नाकामियों, विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। भाजपा देश के युवाओं, छात्रों के गुस्से का सामना नही कर पा रही है। सत्ता के बल पर युवाओं, छात्रों व विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 में सुक्खू की सरकार बनने के तुरंत बाद जेओए आईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया था। इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की पुरानी ली गई कई परीक्षाओं में अनियमितताएं पाए जाने के बाद फरवरी 2023 में इस आयोग को पूरी तरह भंग कर दोषियों को सलाखों के पीछे धकेला। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2025' लागू किया है, जिसके तहत पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को भी नीट व सीबीएसई के पेपर लीक मामलें में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाना व आंदोलनरत छात्रों की मांगों को मानना चाहिए।

शिमला में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। डीसी शिमला ने बताया कि जिला में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से मानदेय आधार पर पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्नियुक्ति से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र विज्ञापन सूचना संख्या SML-EA(474)/Misc.-171175 दिनांक 23 जुलाई, 2026 में उपलब्ध हैं। यह जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है। उपायुक्त ने बताया कि पूर्ण रूप से भरे आवेदन सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों सहित 3 अगस्त, 2026 तक जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त या अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नशे के खिलाफ बिलासपुर प्रशासन सख्त

एनकॉर्ड समिति की बैठक में नशा तस्करी पर मंथन, स्वारघाट नशा मुक्ति केंद्र ने की समीक्षा

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी राहुल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास, जन जागरूकता अभियान तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ गंभीरता से कार्य कर रही है और जिला प्रशासन भी पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से नशा तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है। बैठक में स्वारघाट में स्थापित किए जा रहे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को केंद्र को जल्द क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस दौरान एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में संलिप्त पाए गए नौ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय और कानूनी कार्रवाई की भी समीक्षा की गई तथा नियमानुसार ठोस कार्रवाई जारी रखने को कहा गया। राहुल कुमार ने ग्राम पंचायतों और शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र, करियर काउंसलिंग और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला में पंचायत स्तर पर 27 नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से नशा उन्मूलन अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा। उपायुक्त ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि जिले में एक लाख से अधिक बच्चों, युवाओं और अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है।

सच बोलने पर झूठे मुकद्दमे व भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही सरकार : राजेंद्र राणा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने वीरवार को प्रदेश सरकार पर 2 बड़े मुद्दों को लेकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में सच बोलने वालों पर कार्रवाई और भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण का खेल चल रहा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अढ़ाई साल पहले बनकर तैयार हुए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आज भी बंद पड़ी है। 3 साल से हमीरपुर की जनता सुन रही है कि क्लासें लगेंगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कॉलेज अभी अस्थायी जगह पर चल रहा है और बच्चे वहीं पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने फर्नीचर खरीद में भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फर्नीचर खरीदने का काम सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया था, फिर उनसे छीन लिया गया। अब 20 करोड़ का फर्नीचर 38 करोड़ में खरीदने की तैयारी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में फाइल इसलिए साइन नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार को पता है इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कल को विजिलेंस जांच होगी तो कई लोग अंदर होंगे। यह सब कमीशन के लेन-देन के चक्कर में हो रहा है। टेंडर इस तरह बनाया जा रहा है कि सिर्फ एक कंपनी क्वालीफाई करे। उन्होंने ओपन टेंडर की मांग करते हुए मेडिकल कॉलेज के पास बन रही 3-4 मंजिला पीजी बिल्डिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह किसकी बन रही है? जमीन किसकी है? आने वाले समय में बहुत खुलासे होंगे। मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमीरपुर में टाउन हॉल में गिनती के लोग थे। सरकार के कार्यक्रमों में लोग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनके काम नहीं होते।

अधिसूचना डीसी शिमला ने कहा- सभी दरें प्रति किलोमीटर और प्रति क्विंटल के आधार पर लागू होंगी

सेब की ढुलाई दरें तय कीं, मनमानी वसूली पर होगी कार्रवाई

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सेब सीजन के दौरान ढुलाई को लेकर प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए परिवहन दरें तय कर दी हैं।

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सेब पेटियों की ढुलाई के लिए ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप व आयशर (टाटा 407) वाहनों का परिवहन शुल्क वजन के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने वाले ट्रक, मिनी ट्रक और पिक-अप ऑपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए ढुलाई दर 95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तय की गई है। चंडीगढ़ तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए यह दर एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पिक-अप (चार पहिया) वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर दो रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए दो रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। वहीं आयशर चार पहिया (टाटा 407) वाहनों के लिए एक रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल का परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि ये सभी दरें प्रति किलोमीटर और प्रति क्विंटल के आधार पर लागू होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई ट्रक, मिनी ट्रक या पिक-अप ऑपरेटर यूनियन निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित दरों का उद्देश्य सेब उत्पादकों को राहत देना और ढुलाई व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।

26 जुलाई को बचत भवन में आयोजित होगा जिला स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह

शिमला। जिला प्रशासन शिमला द्वारा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन बचत भवन शिमला में किया जाएगा। समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों व वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी शिमला ने संबंधित अधिकारियों को समारोह के सफल व गरिमामयी आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य व राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन किया जायेगा तथा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस पर आधारित एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही, उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। समारोह में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा एवं पूर्व सैनिक अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे युवाओं एवं आम नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। डीसी ने बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने उपमंडलों में कारगिल वीरों के परिजनों को सम्मानित करें। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसडीएम शिमला (ग्रामीण) एवं सहायक आयुक्त मंजीत शर्मा, उप निदेशक सैनिक कल्याण विभाग अतुल चंबियाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक : अपूर्व देवगन

'वार्तालाप' के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताई 'नशा मुक्ति अभियान' की रूपरेखा

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी में एकदिवसीय जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय 'सूचना प्रसार में सुधार' रहा, जिसके तहत जन-कल्याणकारी योजनाओं, सटीक सूचना के त्वरित प्रसार, फेक न्यूज की चुनौतियों तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला में मुख्यातिथि के रूप में मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन उपस्थित रहे। वहीं, मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजन में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबुद्ध पत्रकारों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सही सूचना का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। उन्होंने पीआईबी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया के बीच संवाद व समन्वय और अधिक सुदृढ़ होता है। उन्होंने आगे कहा कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवा उम्मीदवारों के लिए पीआईबी एक अहम और भरोसेमंद स्रोत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा करते हुए अपूर्व देवगन ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है कि एआई क्या कर सकता है। साथ ही, उन्होंने एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर दिया। आज के समय में खबर और किसी भी सूचना को जल्द प्रकाशित करने की दौड़ पर प्रकाश डालते हुए, देवगन ने कहा कि कोई भी कार्य समय के दबाव के चलते जल्दी में करना, बहुत आसान होता है पर हमें जिम्मेवार होना पड़ेगा क्योंकि यही जल्दबाजी अक्सर सही और सटीक फैसला लेने पर प्रभाव डालती है। कार्यक्रम के विशिष्टातिथि व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने समाज में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'नशा मुक्ति अभियान' की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने युवाओं को सही दिशा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में क़ानून व्यवस्था को क़ायम रखने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यशाला की शुरुआत पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने उपस्थित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए पत्र सूचना कार्यालय की कार्यप्रणाली और 'वार्तालाप' आयोजित करने के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

जून 2027 तक तैयार होगा उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज

लोहाघाट में बन रहा 257 करोड़ की लागत से राज्य का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज

कार्यों की समीक्षा कर जानकारी लेते अधिकारी।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में महिला खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के सुंई छमनियां चौड़ में निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को अगस्त 2027 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉलेज प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा, जहां उन्हें खेल प्रशिक्षण के साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉलेज परिसर में छात्रावास, आवासीय भवन, वॉलीबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान, बहुउद्देश्यीय खेल हॉल सहित कई महत्वपूर्ण खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

अगस्त 2027 तक पूरा होगा काम

लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को अगस्त 2027 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉलेज प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा, जहां उन्हें खेल प्रशिक्षण के साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉलेज परिसर में छात्रावास, आवासीय भवन, वॉलीबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान, बहुउद्देश्यीय खेल हॉल सहित कई महत्वपूर्ण खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

◆ **महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण की ओर**

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रावास ब्लॉक, टाइप-2 और टाइप-3 आवासीय भवनों, खेल मैदानों तथा अन्य निर्माणाधीन संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगे के कार्यों की जानकारी दी।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं और निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

> **निर्माण** कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं और निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। यह परियोजना केवल एक भवन निर्माण नहीं बल्कि राज्य की महिला खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
>
> **-जिलाधिकारी मनीष कुमार**

चकराता में विकसित भारत अभियान का समापन केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े ग्रामीण

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से चकराता में फैलाई गई योजनाओं की जानकारी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के चकराता में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून द्वारा आयोजित तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम का विषय विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया था। इस दौरान चित्र प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रतियोगिताओं और सूचना स्टॉलों के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों और आमजन को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कैंट बोर्ड चकराता के उपाध्यक्ष अनिल चांदना ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान कैंट इंटर कॉलेज चकराता के छात्र-छात्राओं ने भाषण, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं जौनसार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने योग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्रों ने जौनसारी लोक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में आकर्षण बढ़ाया। इस अवसर पर कृषि विभाग और बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और लाभार्थी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

विकसित भारत अभियान के तहत ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में कदम।

युवाओं के सम्मान और भविष्य की लड़ाई लड़ रहा यूकेडी

पेपर लीक के खिलाफ यूकेडी का अभियान जारी, सुप्रीम कोर्ट में रखेगा छात्रों का पक्ष

◆ **नीट पेपर लीक मामले में यूकेडी की पैरवी तेज**

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश और देश के युवाओं से जुड़े पेपर लीक मामलों को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी है। दल का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों से लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

> **आम** जनता और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाना दल की जिम्मेदारी है। युवाओं के साथ अन्याय किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। युवाओं की आवाज को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उठाने की बात होनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश और देश के सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों और न्याय की लड़ाई में दल हर स्तर पर उनके साथ खड़ा रहेगा।
>
> **-देव चंद उत्तराखंडी (उत्तराखंड क्रांति दल के नेता)**

उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि युवाओं को न्याय दिलाना और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। दल के अनुसार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी से मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास टूटता है और उनके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

दल ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में छात्रों के हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से अधिवक्ता राकेश बिंजवाल सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। दल का मानना है कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश और प्रदेश के युवाओं के भविष्य तथा उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है।

युवाओं के हक की लड़ाई में यूकेडी मैदान में

दल ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में छात्रों के हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से अधिवक्ता **राकेश विंजौला** सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। दल का मानना है कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश और प्रदेश के युवाओं के भविष्य तथा उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है।

पौड़ी में 35 करोड़ की लागत से बनेगी बहुमंजिला पार्किंग

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। गुरुवार को विधायक राजकुमार पोरी ने पत्रकार वार्ता में विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। गुरुवार को विधायक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पौड़ी शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास किए जा रहे है। इसी कड़ी में पावर हाउस के पास जल्द ही 35 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर लोनिवि निर्माण खंड ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। कहा कि इस पार्किंग के बन जाने से शहर में खड़े वाहनों को पर्याप्त पार्किंग मिल सकेगी। विधायक ने कहा कि देवार गांव में 50 करोड़ की लागत से बनने वाली एनएससी एकेडमी के लिए पहले चरण के तहत 1 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां एनएसएसी एकेडमी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

लोक भवन पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुरमीत सिंह से की शिष्टाचार भेंट

उत्तराखंड और पंजाब के बीच बेहतर समन्वय पर राज्यपालों ने किया विचार विमर्श

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से गुरुवार को लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों राज्यपालों ने प्रदेशों में संचालित बेहतर योजनाओं और सफल कार्यप्रणालियों के अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी विचार विमर्श किया।

भगवान शिव के चरणों में जनकल्याण की प्रार्थना करते दोनों राज्यपाल।

मुलाकात के दौरान उत्तराखंड और पंजाब में जनकल्याण से जुड़े कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों राज्यपालों ने शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन प्रशासनिक सुधार और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की।

इससे पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लोक भवन परिसर स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश और देशवासियों के सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। मंदिर में विधि विधान से पूजा कर उन्होंने जनमानस के लिए शांति और खुशहाली की प्रार्थना की।

कारोबार वृद्धि में यूको बैंक ने बनाया नया रिकॉर्ड

यूको बैंक ने पहली तिमाही में दर्ज किया शानदार वित्तीय प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन किया है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र कुमार साबू ने तिमाही परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही में बैंक के कारोबार और लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इस अवधि में बैंक का कुल कारोबार बढ़कर 6,05,083 करोड़ रुपये पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर 5.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल ऋण में भी 20.48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 2,72,768 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बैंक ने इस तिमाही में 656 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.05 प्रतिशत अधिक है।

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। सकल एनपीए घटकर 2.08 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.25 प्रतिशत रह गया है। यूको बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने शाखा नेटवर्क को भी मजबूत किया है। बैंक की ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में पहुंच लगातार बढ़ रही है, जिससे अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने शुरू की श्रमिक कल्याण की नई योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की नई योजनाओं का शुभारंभ किया तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दो मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता, मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सामग्री और मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत हाईजीन किट उपलब्ध कराई जाएगी। धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क योग एवं वेलनेस प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 210 बच्चों को आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की निशुल्क जांच, टेली-कंसल्टेशन और तीन माह तक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करेंगी।

श्रावण मास में भंडारा आयोजन से मजबूत होती है भाईचारे की भावना : डॉ . अग्रवाल

राम झूला क्षेत्र में विशाल भंडारे का शुभारंभ, श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। श्रावण मास के पावन अवसर पर विक्रम मालिक चालक संगठन मुनि की रेती राम झूला की ओर से आयोजित विशाल भंडारे का शुभारंभ ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि श्रावण मास भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का विशेष पर्व है। इस महीने में पूजा पाठ के साथ साथ सेवा और परोपकार के कार्यों का भी विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि भंडारे जैसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम लोगों को सेवा कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने आयोजन समिति और विक्रम मालिक चालक संगठन के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि जनसेवा के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। इस अवसर पर ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान मुनि की रेती नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बिजलवान सहित कई जनप्रतिनिधि संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

देहरादून में यूकेडी द्वारा सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल महानगर देहरादून द्वारा महानगर अध्यक्ष प्रबीन रमोला के नेतृत्व में दोपहर 12:30 बजे द्रोण चौक, देहरादून में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित कर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक के विरोध में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं एवं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज तथा देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुबोध उनियाल के आवास के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों द्वारा कथित रूप से जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना के विरोध में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रबीन रमोला ने कहा कि आज देश और प्रदेश का युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है। युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनकी जायज़ मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

रुद्रप्रयाग पुलिस का संध्याकालीन चेकिंग अभियान, नशा तस्करों पर कसा शिकंजा

◆ **कानून व्यवस्था मजबूत करने को सड़कों पर उतरी रुद्रप्रयाग पुलिस**

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पुलिस ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से संध्याकालीन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में जिले की सभी पांचों कोतवालियों रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि ऊखीमठ गुप्तकाशी और सोनप्रयाग की पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच की। अभियान के दौरान पुलिस ने संवेदनशील स्थानों बाजारों बस अड्डों होटल ढाबों और जिला सीमाओं पर बने बैरियरों पर विशेष निगरानी रखी। नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और स्थानों की जांच की गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने तेज गति से वाहन दौड़ाने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान किए गए। शाम के समय पुलिस की पैदल गश्त और सक्रिय मौजूदगी से स्थानीय लोगों तथा तीर्थयात्रियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।

कांवड़ मेले में सुरक्षा का मजबूत इंतजाम 32 अस्थायी अस्पताल होंगे तैयार

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार करीब 5 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले के दौरान 32 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, जहां डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था रहेगी। विशेष रूप से एंटी वेनम और एंटी रेबीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। वन विभाग ने जगजीतपुर और श्यामपुर समेत संवेदनशील वन क्षेत्रों में हाथी और गुलदार की गतिविधियों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का फैसला किया है। कांवड़ मार्गों के आसपास झाड़ियों की सफाई कराई जा रही है और वनकर्मियों की टीमें 24 घंटे गश्त पर रहेंगी। गंगा घाटों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वाटर एंबुलेंस के साथ तैनात रहेंगी। वहीं, मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन ने कांवड़ मेले के दौरान कुंभ से जुड़े नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित न हो। साथ ही शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

उत्तराखंड में बढ़ा–भूस्खलन का खतरा 18 .47 प्रतिशत क्षेत्र हाई रिस्क जोन में

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि राज्य का करीब 18.47 प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन के लिहाज से उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आता है। खासतौर पर उत्तरकाशी और चमोली जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षेत्रों में प्राकृतिक परिस्थितियां और बदलता मौसम भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह अध्ययन शिव नादर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की आपदा प्रबंधन प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने किया है। शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के करीब 53 हजार 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। इसमें राज्य के सभी जिलों को शामिल किया गया। अध्ययन में आधुनिक तकनीकों की मदद से उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां भूस्खलन की आशंका अधिक बनी रहती है।

शोध के अनुसार उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय तथा मध्य हिमालय क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इन इलाकों में लगातार बारिश तीखी ढलान कमजोर भूगर्भीय संरचना और पहाड़ी भू आकृति भूस्खलन के खतरे को बढ़ाती है। इसके अलावा वनस्पति में बदलाव और मानव गतिविधियों के कारण भी पहाड़ों की स्थिरता प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरकाशी और चमोली जैसे जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर योजना और वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत है। वहीं हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के तराई भाबर क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा सबसे कम पाया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण कार्य सड़क चौड़ीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य में खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में समय रहते चेतावनी प्रणाली मजबूत करना और सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है।

भारी बारिश बढ़ा रही चिंता, कई क्षेत्र जोखिम श्रेणी में।

अमर शहीद वत्स की 101वीं जयंती पर होगा समारोह

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। अमर शहीद जगदीश वत्स की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर 25 जुलाई को हरिद्वार प्रशासन की ओर से पुल जटवाड़ा स्थित जगदीश वत्स पार्क में भव्य स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में जिले के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्य, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों की गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के अनुरोध पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। समारोह में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक व प्रदीप बत्रा, विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, जिला विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्रा सहित कई अतिथियों के उपस्थित रहने की संभावना है। समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि इस अवसर पर हरिद्वार के उन वरिष्ठ पत्रकारों को जगदीश वत्स सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से समाज के सामने रखा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत जन्दडू
विकास खण्ड (बमसन टौणी) जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

निविदा सूचना

वितीय वर्ष 2026-27 (05.08.2026 से 31.03.2027) के विकास कार्य हेतू क्रेशर रेत, दरिया रेत, क्रेशर बजरी 10,20,40 mm, शाइन बोर्ड लिखाई सहित (2.6*3) प्रति बोर्ड, सीमेंट कैरिज लोडिंग अनलोडिंग सहित प्रति बैग (सुजानपुर से जन्दडू), JCB द्वारा कटाई हार्ड & सॉफ्ट रॉक (प्रति घन मीटर), निर्माण सामग्री ढुलाई मुख्य सड़क से निर्माण स्थल तक (प्रति बैग /प्रति क्यूबिक मीटर), शटरिंग स्टील, शटरिंग प्लेट व शटरिंग लकड़ी छत व दीवार (प्रति स्क्वायर फीट), सेटरिंग लकड़ी व डाब (प्रति रनिंग मीटर), बोर्ड ढुलाई मुख्य सड़क से निर्माण स्थल तक (प्रति बोर्ड), ईट, सीमेंट बेंच (स्टैण्डर्ड/क्लासिक) आदि निर्माण सामग्री हेतू निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म का अपना GST नंबर व अपनी Commercial गाड़ी होना अनिवार्य है। रेता, बजरी, पत्थर की अदायगी प्रपत्र X व W बिल के साथ देने पर ही होगी। सामग्री का मूल्य वर्क साईट तक FOR मान्य होगा। पंचायत की मांग समय पर पूरा न करने अथवा घटिया सामग्री होने पर निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार पंचायत का होगा। निविदाएं मोहर बंद लिफ़ाफ़े में दिनांक 05/08/2026 से पहले पंजीकृत डाक द्वारा अथवा पंचायत कार्यालय में कार्य दिवस पर स्वयं पहुंचाई जा सकती है। सभी निविदाएं दिनांक 06/08/2026 को प्रातः 11:30 बजे पंचायत कार्यालय में खोली जायेंगी, फर्म उस दिन हाजिर रहे ,अलग से कोई पत्र नहीं निकाला जायेगा।

प्रधान /सचिव
कार्यालय पंचायत सामुदायिक केन्द्र जन्दडू

चंडीगढ़ में सांसद की पहल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लंबित भुगतान हुआ पूरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतजार कर रहे हजारों पात्र लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के तहत मई 2026 तक लंबित सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद मनीष तिवारी को भेजे गए आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी है। इससे लंबे समय से लंबित पेंशन भुगतान को लेकर चल रही शिकायतों पर फिलहाल विराम लग गया है।

दरअसल, सांसद मनीष तिवारी ने 12 फरवरी 2026 को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा था कि बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी कई महीनों से पेंशन की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की थी।

सांसद द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। प्रशासन की ओर से मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लंबित सभी मामलों का निस्तारण करते हुए मई 2026 तक की बकाया राशि पात्र लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। प्रशासन ने दावा किया है कि फिलहाल मई 2026 तक का कोई भी बकाया शेष नहीं है और सभी पात्र लोगों को निर्धारित राशि उपलब्ध करा दी गई है।

चन्नी की दूरी से पंजाब कांग्रेस पर उठे सवाल

पंजाब कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व एकजुटता और संगठन की रणनीति के अनुसार चलने का दे रही संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़े दो घटनाक्रमों ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। संसद परिसर में सामने आए एक वायरल वीडियो और युवाओं के मुद्दों व पेपर लीक के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान चन्नी की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

संसद परिसर में वायरल हुए वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते नजर आए। वहीं, वीडियो में चरणजीत सिंह चन्नी कुछ दूरी पर अलग खड़े दिखाई दिए। इस दृश्य को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही संगठनात्मक स्थिति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इसके बाद युवाओं के मुद्दों और पेपर लीक के विरोध में संसद से निकाले गए मार्च के दौरान भी चन्नी को कोई विशेष राजनीतिक भूमिका मिलती हुई दिखाई नहीं दी। इन घटनाओं के बाद चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस नेतृत्व पंजाब इकाई के नेताओं को संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व का संदेश देना चाहता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

संगठन को प्राथमिकता देने का संकेत : राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से अलग-अलग मुद्दों पर व्यक्तिगत राजनीतिक रुख सामने आता रहा है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व यह संकेत देना चाहता है कि पार्टी में किसी एक नेता की व्यक्तिगत छवि से ज्यादा संगठन का निर्णय और सामूहिक रणनीति महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों के अनुसार, कांग्रेस आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश इकाई में एकजुटता बनाए रखना चाहती है। पार्टी नेतृत्व का प्रयास है कि सभी नेता तय रणनीति के अनुसार काम करें और सार्वजनिक मंचों पर अलग-अलग राजनीतिक लाइन या बयानबाजी से बचें। माना जा रहा है कि यह संदेश केवल चन्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए है।

दलित चेहरे के रूप में पहचान : चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के प्रमुख दलित नेताओं में शामिल हैं। वर्ष 2021 में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।

चुनाव हारने के बाद पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर लगातार बदलाव होते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी समय-समय पर पार्टी के भीतर मतभेद और खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेताओं की भूमिका को लेकर भी संगठनात्मक चर्चाएं होती रही हैं।

वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने नहीं दी प्रतिक्रिया : हाल के महीनों में चरणजीत सिंह चन्नी के कुछ बयानों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में संसद परिसर की तस्वीरों और वीडियो को इन अटकलों को और बढ़ावा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने न तो वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि किसी नेता को कोई विशेष संदेश दिया गया है। इसलिए, फिलहाल इन घटनाओं को राजनीतिक विश्लेषण और पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के आधार पर ही देखा जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

हाउसफेड आवंटी 22 वर्षों से आशियाने को तरसे

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। हाउसफेड की सेक्टर-79 आवासीय योजना के 52 आवंटी पिछले करीब 22 वर्षों से अपने फ्लैटों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2004 में ड्रा के माध्यम से फ्लैट आवंटित होने के बावजूद उन्हें अब तक आशियाना नहीं मिल पाया है।

आवंटियों का आरोप है कि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बाद भी प्रशासनिक देरी और विभागीय तालमेल की कमी के कारण कब्जा प्रक्रिया अटकी हुई है। हाउसफेड ने वर्ष 2004 में 220 फ्लैटों के लिए ड्रा निकाला था। भूमि विवाद के कारण परियोजना प्रभावित हुई। वर्ष 2014 में 168 फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया, जबकि 52 फ्लैट लंबित रह गए। वर्ष 2023 में निर्माण कार्य मार्कफेड को सौंपा गया और जून 2024 तक कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन जुलाई 2026 तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। संघर्ष समिति के सदस्य रविंदर डोगरा ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी नहीं होने से आवंटी परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जल्द कब्जा दिलाने की मांग की है।

यूके वर्क परमिट के नाम पर पूर्व सैनिक से ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। यूके का वर्क परमिट दिलाने के नाम पर पूर्व सैनिक से 4.16 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में फेज-3ए स्थित वीज़ा पैलेस इमिग्रेशन के मालिक समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सुखवीर सिंह निवासी मोरिंडा ने आरोप लगाया कि मई से अक्तूबर 2025 के बीच परिवार सहित यूके भेजने का झांसा देकर उनसे किस्तों में रकम ली गई, लेकिन न तो वर्क परमिट मिला और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस ने अमरजीत सिंह, साहिल, प्रीत, नवनीत, वाणी, अरमान और दो अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

एरोट्रोपोलिस प्लॉट कब्जे में देरी से भू-मालिक नाराज

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। गमाडा की एरोट्रोपोलिस परियोजना के पहले चरण के भू-मालिक विकसित प्लॉटों का कब्जा नहीं मिलने से नाराज हैं। वर्ष 2021 में एलओआई जारी होने के बावजूद ए से डी ब्लॉक के लाभार्थियों को अब तक प्लॉट नहीं मिले हैं। वहीं, गमाडा ने दूसरे चरण के ई से जे ब्लॉक के लिए 3522.98 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भू-मालिकों ने पहले चरण के लंबित मामलों को निपटाने की मांग की है। गमाडा के मुख्य अभियंता अजय गर्ग ने बताया कि विकास कार्य जारी हैं और मार्च 2027 से कब्जा देने का लक्ष्य रखा गया है।

अविश्वास प्रस्ताव के बाद अजीत सिंह पद से हटे

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। नगर निगम सफाई सेवक मजदूर यूनियन में अंदरूनी विवाद के बाद अध्यक्ष अजीत सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया। महासचिव परविंदर सिंह को नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत सिंह के व्यवहार से यूनियन की छवि प्रभावित हो रही थी। बैठक में यूनियन ने नगर निगम को कमरा नंबर-3 भी वापस सौंप दिया।

सात साल पुराने हादसे में आरोपी को दो साल सजा

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। करीब सात वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए परविंदर सिंह उर्फ पिंदरा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दो वर्ष और धारा 279 व 337 के तहत छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 15 जनवरी 2016 का है, जब तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार दो युवतियों को टक्कर मार दी थी। हादसे में मनदीप कौर की मौत हो गई थी। अदालत ने घायल हरमीत कौर की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से साबित हुआ कि हादसे के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

चंडीगढ़ में ब्रिक्स की स्वास्थ्य बैठक संपन्न वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को मिलेगा विस्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के समापन पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नौ प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। इनमें टीबी रिसर्च नेटवर्क को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ सिस्टम का विस्तार और पारंपरिक एवं समेकित चिकित्सा को बढ़ावा देना प्रमुख रहे।

केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि ब्रिक्स देशों ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। पिछले एक दशक में आयुष उत्पादों के निर्यात में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देशों के बीच ज्ञान, अनुसंधान और आधुनिक तकनीकों का आदान-प्रदान बेहद आवश्यक है। संक्रामक और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, महामारी से निपटने की तैयारियों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, किफायती दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने माना कि डिजिटल तकनीकों के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। बैठक में सदस्य देशों ने चिकित्सा अनुसंधान, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और सफल अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

साढ़े सात लाख की चोरी होने पर कई दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मनीमाजरा थाना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दर्शनी बाग निवासी एक कारोबारी के घर से करीब साढ़े सात लाख रुपये मूल्य का पांच तोले का सोने का हार और 40 हजार रुपये नकद चोरी होने के बावजूद कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की है और न ही संदिग्धों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध युवतियों की तस्वीरें और उनके बारे में अहम जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई केवल जांच तक सीमित है।

दर्शनी बाग निवासी आशीष शर्मा ने बताया कि वह पैकिंग के गत्ते के डिब्बे बनाने का कारोबार करते हैं। उन्होंने हाल ही में रायपुर रानी में एक प्लॉट का सौदा किया था, जिसके बयाने के लिए पांच तोले का सोने का हार बेचने का फैसला किया था। इस संबंध में उनकी एक ज्वेलर से बातचीत भी हो चुकी थी। 16 जुलाई की दोपहर उन्होंने घर की अलमारी से हार और 40 हजार रुपये निकालकर बेड पर रखे और कुछ मिनट के लिए बाथरूम चले गए। उस समय उनकी मां नीरू शर्मा घर के दूसरे कमरे में मौजूद थीं। करीब पांच मिनट बाद जब वह लौटे तो बेड पर रखा हार और नकदी दोनों गायब थे।

घटना के तुरंत बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दो युवतियां घर में प्रवेश करती और कुछ देर बाद बाहर निकलती दिखाई दीं। फुटेज में उनके आने और जाने का समय भी साफ नजर आ रहा है। आशीष का कहना है कि उन्होंने उसी दिन यह फुटेज मनीमाजरा थाना पुलिस को सौंप दी थी।

पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की सुस्त कार्रवाई के कारण उन्हें खुद ही संदिग्ध युवतियों की तलाश करनी पड़ी। उनका दावा है कि उन्होंने दोनों महिलाओं का सुराग भी लगा लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्हें हिरासत में लिया गया और न ही अब तक मामला दर्ज किया गया।

आईडीएफसी बैंक घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, चंडीगढ़ और लुधियाना से अहम साक्ष्य बरामद

पांच स्थानों पर छापेमारी, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय दस्तावेज सीबीआई ने किए जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ नगर निगम के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को चंडीगढ़ और लुधियाना में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई सरकारी धन के फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और संदिग्ध बैंक लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये के गबन से जुड़े मामले में की गई।

सीबीआई के अनुसार, जांच दल ने कुल पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सीएससीएल के कर्मचारी अनुभव मिश्रा का ठिकाना तथा जांच के दायरे में आई कुछ निजी कंपनियों के कार्यालय शामिल हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं।

जांच एजेंसी ने जिन सामग्रियों को जब्त किया है, उनमें स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, वित्तीय लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। सीबीआई इन डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण कर रही है ताकि धन के प्रवाह, लेनदेन की प्रक्रिया और इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

यह मामला हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के सरकारी धन के कथित गबन से जुड़ा है। आरोप है कि हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के लगभग 657 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट तैयार कर तथा धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजेक्शनों के माध्यम से बैंक खातों से निकाला गया। इसके बाद इस राशि को कई शेल कंपनियों के जरिए अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर धन के स्रोत को छिपाने का प्रयास किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान एजेंसी ने बैंकिंग रिकॉर्ड, सरकारी फाइलों और वित्तीय दस्तावेजों की गहन पड़ताल की, जिसके आधार पर कई लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

सीबीआई अब तक हरियाणा से जुड़े मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन कर्मचारी, दो निजी कंपनियां तथा छह निजी व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि इन सभी की भूमिका सरकारी धन के अवैध हस्तांतरण और वित्तीय धोखाधड़ी में सामने आई है।

कोकीन तस्करी साजिश में वांटेड हरमनवीर सिंह हुआ गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) की ओर से वांटेड घोषित किए गए हरमनवीर सिंह को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने स्टॉकटन से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के साथ मिलकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच कोकीन और मेथएम्फेटामीन की तस्करी की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं।

◆ तीन देशों में ड्रग तस्करी के आरोपों में पकड़ा गया हरमनवीर सिंह

एफबीआई के अनुसार, हरमनवीर सिंह लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर में था। आरोप है कि वह रविंदर ढंडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो उत्तरी अमेरिका के कई देशों में सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क के लिए काम करता था। बुधवार सुबह कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने स्टॉकटन में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस संगठित अपराध समूह का आधार कनाडा के वैंकूवर में बताया जाता है। आरोप है कि यह गिरोह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करता था। अब हरमनवीर सिंह से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क, इसके सदस्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

अमेरिका और कनाडा की जांच एजेंसियां पिछले कुछ वर्षों से सीमा पार सक्रिय अपराध और ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त अभियान चला रही हैं।

मुहिम पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में दो माह तक चलेगा अभियान, समाज के सभी वर्गों का मिलेगा सहयोग

खेल सामग्री देकर युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने वीरवार को लोकभवन पंजाब में समाज को नशामुक्त बनाने और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से 'खेल का उपहार, नशे पर प्रहार' अभियान का शुभारंभ किया। कर्तव्यनिष्ठ एवं नशा मुक्ति चेतना संघ के संयुक्त तत्वावधान में शुरू किए गए इस दो माह लंबे अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर जरूरतमंद बच्चों तक खेल सामग्री पहुंचाना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

अभियान के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति केवल एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चुनौती है। इससे निपटने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यदि बच्चों और युवाओं को खेलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाकर देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं।

अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन बच्चों की पहचान की जाएगी, जिनमें खेल प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उद्योगपतियों, व्यापारियों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, खिलाड़ियों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम नागरिकों से सहयोग लिया जाएगा।

अभियान के दौरान क्रिकेट बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन रैकेट, खेल किट, खेल जूते तथा अन्य आवश्यक खेल सामग्री एकत्रित की जाएगी।

इसके बाद इन्हें जरूरतमंद बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में 10 हजार लोगों को इस जनअभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बड़ी संख्या में बच्चों तक सहायता पहुंचाई जा सके। आयोजकों के अनुसार यह पहल केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी।

नशा मुक्ति चेतना संघ के सहयोग से इसे पूरे पंजाब में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों तक भी खेल सामग्री पहुंचाई जाएगी। उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की खेल प्रतिभा के विकास में बाधा न बने। अभियान के संयोजक संजीव राणा ने कहा कि 'खेल का उपहार, नशे पर प्रहार' केवल खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जनआंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर कर खेल, अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जब समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए आगे आते हैं, तब सकारात्मक बदलाव संभव होता है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों में उपयोग योग्य खेल सामग्री, नई या अच्छी स्थिति में मौजूद खेल उपकरण अथवा आर्थिक सहयोग देकर इस अभियान का हिस्सा बनें। उनका कहना था कि एक छोटी-सी मदद किसी प्रतिभाशाली बच्चे के सपनों को नई उड़ान दे सकती है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस अभियान के माध्यम से न केवल हजारों बच्चों को खेल सामग्री मिलेगी, बल्कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समाज में स्वस्थ, सकारात्मक तथा खेल संस्कृति को भी नई मजबूती मिलेगी।

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण को मोहाली में जल्द बनेंगे 13 फीडिंग प्वाइंट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और काटने की घटनाओं के बीच मोहाली नगर निगम ने शहर में 13 प्रस्तावित सामुदायिक कुत्ता भोजन स्थल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निगम ने इन स्थानों की प्रारूप सूची जारी करते हुए आम नागरिकों, आवासीय कल्याण समितियों, पशु प्रेमियों, सामाजिक संगठनों तथा अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 1 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इन स्थानों का चयन विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण और एक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से किया गया है। चयन के दौरान सुरक्षा, लोगों की सुविधा, आवारा कुत्तों की आवाजाही तथा यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया कि भोजन करने की व्यवस्था से आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी या विवाद का सामना न करना पड़े।

प्रत्येक प्रस्तावित स्थल का विवरण संबंधित क्षेत्र, प्रमुख पहचान और भौगोलिक स्थिति के साथ निगम के सार्वजनिक सूचना मंच पर उपलब्ध कराया गया है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां निर्धारित माध्यमों से भेज सकते हैं। प्राप्त सभी सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और आवश्यक संशोधन के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मानव और पशु के बीच बढ़ते टकराव को कम करना तथा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब पंजाब में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2025 में राज्यभर में 3.34 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक आंकड़ा माना गया। इसी अवधि में रेबीज से 8 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई, जिससे स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अमृतसर, लुधियाना और पटियाला शामिल रहे। अमृतसर में अकेले 58 हजार से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा।

नीट मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

भाजपा ने नीट मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, प्रदर्शन के दौरान केवल सिंह ढिल्लों समेत कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

भारतेंदु संवाददाता, बठिंडा

भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने कांग्रेस पर नीट मामले को लेकर राजनीति करने, अराजकता फैलाने और छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केवल सिंह ढिल्लों, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया। बाद में सभी को सेक्टर-11 पुलिस स्टेशन ले जाकर रिहा कर दिया गया।

हिरासत में लिए जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस जवाबदेही से बचने के लिए आंदोलन की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

ढिल्लों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश यात्राओं से लौटने के बाद राहुल गांधी ने छात्रों के नाम पर राजनीतिक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वास्तव में छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि वह राजनीतिक विवाद खड़ा करना चाहती है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट मामले में शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए दोनों दलों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने फरीदकोट में कथित फार्मेसी परीक्षा नकल मामले को लेकर दोनों पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पंजाब में परीक्षा घोटालों के समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोलतीं।

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच कई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक हुए, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, उन्होंने मोदी सरकार की कार्रवाई को तेज और पारदर्शी बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि पुलिस कार्रवाई, बैरिकेडिंग और हिरासत से पार्टी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा देशभर में कांग्रेस की कथित छात्र विरोधी राजनीति को उजागर करती रहेगी और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर छात्रों के हितों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वहीं, भाजपा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के समर्थन में नारे लगाए और कांग्रेस से जवाबदेही तय करने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पठानकोट जमीन घोटाले में ईडी की जांच तेज

ईडी जांच में 92 एकड़ सरकारी जमीन मामले से जुड़े कई खुलासे आए सामने

भारतेंदु संवाददाता, पठानकोट।

पंजाब के पठानकोट में 92 एकड़ शामलात (सरकारी) जमीन से जुड़े करीब 200 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद कई अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसी इस मामले में जमीन हस्तांतरण, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से नेटवर्क की जांच कर रही है।

मामले के अनुसार रावी नदी के किनारे स्थित 92 एकड़ जमीन को लेकर कथित तौर पर महज 96 घंटे के भीतर बड़े प्रशासनिक फैसले लिए गए। आरोप है कि 28 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे तत्कालीन बीडीपीओ कुलदीप सिंह को अचानक प्रमोट कर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बनाया गया और उन्हें अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) का चार्ज भी सौंप दिया गया।

चार्ज संभालने के तीसरे दिन 27 फरवरी 2023 को कुलदीप सिंह ने इस शामलात जमीन को छह महिलाओं के नाम करने का आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि इस दौरान पंचायत का पक्ष नहीं सुना गया और सभी दस्तावेजों की पूरी जांच भी नहीं की गई। इसके अगले ही दिन अधिकारी रिटायर हो गए।

गोल पंचायत ने इस मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत दी थी। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर ने अगस्त 2023 में रिटायर्ड अधिकारी कुलदीप सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ जालसाजी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया था।

96 घंटे में हुए फैसलों पर ईडी ने शुरू की गहन पड़ताल

अब जुलाई 2026 में ईडी ने पठानकोट में 16 ठिकानों पर छापेमारी कर जांच को आगे बढ़ाया है। कार्रवाई के दौरान करीब 1.75 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए और 91.34 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज किया गया है।

ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन हस्तांतरण के पीछे किसका दबाव था और इससे किन लोगों को लाभ पहुंचा। इसके अलावा रावी नदी क्षेत्र में कथित अवैध खनन की भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार कुछ स्टोन क्रशर कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि बिना अनुमति और रॉयल्टी भुगतान के रेत व अन्य खनिजों का कारोबार किया गया। ईडी अधिकारियों की नजर अब प्रशासनिक अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका पर है। आने वाले दिनों में मनी ट्रेल और दस्तावेजों के आधार पर जांच का दायरा और बढ़ सकता है। ईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। एजेंसी वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है।

ईजी रजिस्ट्री सिस्टम में तकनीकी दिक्कत से जालंधर में रजिस्ट्रेशन कार्य हुआ प्रभावित

ओटीपी समस्या के कारण सैकड़ों लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर।

पंजाब सरकार की ओर से लागू किए गए ईजी रजिस्ट्री सिस्टम में लगातार किए जा रहे तकनीकी बदलावों के चलते रजिस्ट्री प्रक्रिया एक बार फिर प्रभावित हुई है। बुधवार को ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण जालंधर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में करीब दो घंटे तक रजिस्ट्रेशन का काम बाधित रहा। सिस्टम में लॉगिन नहीं होने के कारण अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह रुक गई। इससे रजिस्ट्री करवाने पहुंचे सैकड़ों लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार ईजी रजिस्ट्री सिस्टम में हाल ही में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए थे। इन बदलावों के बाद सब-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहे थे। ओटीपी नहीं मिलने के कारण अधिकारी सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाए और दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

तकनीकी समस्या का असर कार्यालयों में बने हेल्प डेस्क पर भी देखने को मिला, जहां ऑनलाइन टोकन जारी करने का काम बंद हो गया। सुबह निर्धारित समय पर अप्वाइंटमेंट लेकर पहुंचे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। कई लोग अपने जरूरी काम पूरे नहीं होने के कारण परेशान नजर आए। लोगों का कहना था कि वे दूर-दराज के इलाकों से समय निकालकर कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ा।

सब-रजिस्ट्रार-1 कार्यालय में करीब 130 ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक थीं, लेकिन तकनीकी बाधा के कारण देर शाम तक केवल 111 दस्तावेजों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका। इसी तरह सब-रजिस्ट्रार-2 कार्यालय में 80 अप्वाइंटमेंट में से केवल 66 दस्तावेजों की ही ऑनलाइन मंजूरी मिल पाई। तकनीकी समस्या दूर होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने अतिरिक्त समय तक कार्यालय में रुककर लंबित मामलों का निपटारा किया।

अमृतसर में 6.72 किलो हेरोइन बरामद युवक गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र में पुलिस ने एंटी-ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6.72 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शमशेर सिंह निवासी गांव बचीविंड, थाना लोपोके के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अजनाला में बीएसएफ कैंपस के सामने स्थित सिम्बा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी के किराए के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से 6.72 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क तथा अन्य जुड़े लोगों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है।

बरनाला लाठीचार्ज से नाराज सफाई कर्मचारियों ने किया आंदोलन

सफाई कर्मचारियों ने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। बरनाला में सफाई कर्मचारियों और अन्य प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरदासपुर में सफाई कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया और पिट सियापा कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि बरनाला में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में कई कर्मचारी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घायल कर्मचारियों में महिला कर्मचारी भी शामिल हैं और एक गर्भवती महिला के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। कर्मचारियों ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

यूनियन नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक कर्मचारी को अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहिए, न कि बल प्रयोग के जरिए।

प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार से मांग की कि बरनाला लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। इसके साथ ही घायल कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया जाए और कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की आवाज को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उनमें रोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के अंत में यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बरनाला घटना पर भड़के कर्मचारी, पुतला फूंक कर जताया विरोध

डीसी दफ्तर में कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज ठप

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। अपनी मांगों को लेकर पंजाब डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन ने 23 जुलाई से 26 जुलाई तक चार दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके तहत गुरदासपुर में डीसी कार्यालय के कर्मचारियों ने गुरुवार से कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील और सब-तहसील कार्यालयों में होने वाले सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है।

हड़ताल के कारण विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों में पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

लोगों ने बताया कि वे दूर-दराज के इलाकों से अपने काम करवाने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च हो रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि कर्मचारी यूनियन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

वहीं कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सरकार की ओर से मांगों को लेकर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।

18 चालान लंबित मिलने के बाद विभाग ने नियम उल्लंघन पर तेज की कार्रवाई

बिना स्टेट टैक्स चल रही टूरिस्ट बस पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, बरनाला। पंजाब में बिना स्टेट टैक्स और जरूरी परमिट के चल रही बाहरी राज्यों की टूरिस्ट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। बरनाला में हुई ताजा कार्रवाई के दौरान ग्वालियर से श्री अमृतसर साहिब जा रही एक टूरिस्ट बस को नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़ा गया। विभाग ने बस को इंपाउंड कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा करने के बाद ही बस को छोड़ा गया।

जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग की टीम ने टूरिस्ट बस नंबर क75 1855 की जांच की। जांच में सामने आया कि बस ने पंजाब में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य स्टेट टैक्स जमा नहीं कराया था। इसके बाद अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बस का चालान किया।

ए.आर.टी.ओ. जसनजोत सिद्धू ने बताया कि यह मामला केवल एक चालान तक सीमित नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले दो से तीन वर्षों में इसी बस के करीब 18 चालान किए जा चुके हैं। इनमें से केवल चार चालानों का ही भुगतान किया गया है, जबकि विभिन्न राज्यों में करीब 1.30 लाख रुपये के चालान अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वाहन मालिक लगातार नियमों की अनदेखी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बिना परमिट और टैक्स के चलने वाली बसों का मुद्दा हाल ही में पंजाब विधानसभा में भी उठाया गया था।

स्कूल मार्ग पर जलभराव से विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई क्षेत्रों में जलभराव और खराब सड़कों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव गुरदास नंगल में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने टूटी सड़क अब तालाब का रूप ले चुकी है, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है।

स्कूल के सामने सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण सुबह स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैदल आने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते-मोजे खराब हो जाते हैं।

जेल में तैनात मेडिकल ऑफिसर नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार, जांच शुरू

भारतेंदु संवाददाता, तरनतारन। पंजाब की केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जेल में तैनात एक मेडिकल ऑफिसर को तलाशी के दौरान नशीले पदार्थ, मोबाइल फोन और नकदी सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब के सहायक सुपरिंटेंडेंट कुलजीत सिंह ने बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचे मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनमोलप्रीत सिंह की तलाशी लेने की कोशिश की। इस दौरान डॉक्टर ने अपने बैग की तलाशी करवाने से इनकार कर दिया।

इसके बाद जेल प्रशासन की टीम ने डॉक्टर के बैग और उसकी आई-20 कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 997 लाल रंग के कैप्सूल, 1,490 अन्य कैप्सूल, 2,050 गोलियां, 53 ग्राम चरस जैसा पदार्थ, दो मोबाइल फोन और 2,630 रुपये की नकदी बरामद हुई।

पुलिस ने मौके पर ही डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना श्री गोइंदवाल साहिब में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी कर रही है। पुलिस रिमांड के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आरोपी डॉक्टर कब से जेल के अंदर प्रतिबंधित सामान पहुंचा रहा था।

रावी और उज्ज नदियों में उफान, गुरदासपुर सीमावर्ती गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र दोरांगला के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार बरसात के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सीमा से सटे गांवों के लोगों को आशंका है कि कहीं पिछले वर्ष जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा न बन जाए।

जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित आदी, चौंतरा और सलाच सहित कई गांवों में नोमणी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा रावी और उज्ज नदियों में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ने से सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। कई जगहों पर पानी सड़कों तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों को दैनिक कार्यों के लिए आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव आदी में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीएसएफ की कुछ चौकियों तक जाने वाले संपर्क मार्गों पर भी पानी भर गया है। इससे बीएसएफ जवानों और अधिकारियों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के बाद नहरों और नोमणी नालों की समय पर सफाई नहीं कराई गई। इसी कारण इस बार बारिश के दौरान पानी की निकासी प्रभावित हो रही है और कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए और पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। उनका कहना है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रशासन से लोगों ने नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की अपील की है, ताकि संभावित खतरे से बचाव किया जा सके।

सियासी एंट्री पंजाबी अभिनेता के अकाली दल में शामिल होने से संगठन को मिलेगी नई ऊर्जा

पंजाबी अभिनेता रब्बी कंडोला ने राजनीति में शुरू की नई पारी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में चुनावी गतिविधियों के बीच पंजाबी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता रब्बी कंडोला ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। गुरुवार को उन्होंने सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाली अकाली दल वारिस पंजाब दे की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने उनके शामिल होने को संगठन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे पार्टी की सामाजिक पहुंच बढ़ेगी और युवाओं के बीच संगठन को मजबूती मिलेगी।

सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने रब्बी कंडोला का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रब्बी कंडोला के पार्टी में शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। उनकी लोकप्रियता और पंजाबी फिल्म जगत में पहचान पार्टी की विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने में रब्बी कंडोला की भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है।

पंजाब के मुद्दों से प्रभावित होकर जुड़े : पार्टी की सदस्यता लेने के बाद रब्बी कंडोला ने कहा कि वह अकाली दल वारिस पंजाब दे की विचारधारा और पंजाब के हितों को लेकर किए जा रहे कार्यों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा, संस्कृति और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के प्रयासों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया।

फिल्म जगत के चेहरे की एंट्री से युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी

उन्होंने कहा कि पंजाबी मातृभाषा के संरक्षण और प्रचार की दिशा में काम करना जरूरी है। इसके अलावा पंजाब के लोगों की समस्याओं और अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी समय की जरूरत है। उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर काम करने और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही।

फिल्मी दुनिया के बाद राजनीतिक सफर शुरू : रब्बी कंडोला पंजाबी फिल्म उद्योग का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई है। लंबे समय तक मनोरंजन क्षेत्र में सक्रिय रहने के बाद अब उन्होंने राजनीति में नई पारी की शुरुआत की है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, चुनावी माहौल के बीच किसी लोकप्रिय फिल्म कलाकार का किसी राजनीतिक दल से जुड़ना संगठन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि रब्बी कंडोला की लोकप्रियता से युवाओं और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे।

शुक्रवार की महिमा, धार्मिक आस्था, ज्योतिषीय महत्व और जीवन को सफल बनाने वाली प्रेरणाएं

डॉ. पीसी कौंडल
गांव ददोह, डा. धावन, तहसील बल्ह जिला मंडी (हि.प्र.)

सप्ताह के सातों दिनों का अपना अलग महत्व माना जाता है। प्रत्येक दिन किसी न किसी ग्रह और देवी देवता से जुड़ा हुआ है तथा भारतीय संस्कृति में इन दिनों के अनुसार पूजा पाठ और जीवनशैली का विशेष स्थान है। शुक्रवार ऐसा ही एक शुभ और मंगलकारी दिन माना जाता है। यह दिन धन समृद्धि सुख शांति प्रेम सौंदर्य और वैभव का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शुक्रवार का संबंध मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और माता संतोषी से जोड़ा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

शुक्रवार का नाम संस्कृत के शब्द शुक्र से निकला है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य कला संगीत सौंदर्य प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। यही कारण है कि इस दिन को शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। विवाह की बातचीत नया व्यवसाय शुरू करना घर की खरीदारी या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी कई लोग शुक्रवार को शुभ मानते हैं।

हिंदू धर्म में शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को धन समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन में आर्थिक उन्नति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। घर और कार्यस्थल की सफाई करना दीपक जलाना और माता लक्ष्मी की आरती करना इस दिन की प्रमुख परंपराओं में शामिल है।

कई स्थानों पर शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत भी रखा जाता है। संतोषी माता की पूजा का मुख्य संदेश संतोष धैर्य और विश्वास है। इस व्रत को करने वाले श्रद्धालु खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करते और परिवार की सुख शांति तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय है लेकिन पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ इसे करते हैं।

भारतीय संस्कृति में शुक्रवार केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है। सप्ताह भर के कार्यों के बाद यह दिन परिवार के साथ समय बिताने और आने वाले अवकाश की तैयारी का अवसर भी बनता है। लोग इस दिन घर की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और सप्ताहांत की योजनाएं बनाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी शुक्रवार कई बाजारों के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन खरीदारी करने वालों की संख्या अधिक रहती है।

इस्लाम धर्म में भी शुक्रवार का विशेष महत्व है। इस दिन को जुमा कहा जाता है और इसे सप्ताह का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मुसलमान बड़ी संख्या में मस्जिदों में एकत्र होकर जुमे की विशेष नमाज अदा करते हैं और समाज की भलाई शांति तथा मानवता के लिए दुआ करते हैं। जुमे का दिन भाईचारे समानता और एकता का संदेश देता है।

ईसाई धर्म में शुक्रवार का भी विशेष महत्व है। विशेष रूप से गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन त्याग प्रेम और मानवता की सेवा का संदेश देता है। इस प्रकार शुक्रवार विभिन्न धर्मों में अलग अलग रूपों में आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक बनकर सामने आता है।

ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में कला संगीत अभिनय फैशन विलासिता और संबंधों को प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो उसे जीवन में सुख सुविधाएं सम्मान और आर्थिक उन्नति मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है। इसलिए कई लोग शुक्रवार के दिन दान पुण्य सफेद वस्तुओं का दान और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ मानते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बारिश के मौसम में चाट पकौड़ी और फास्ट फूड का बढ़ता आकर्षण, लेकिन स्वच्छता की बढ़ रही चिंता

राजेंद्र पालमपुरी
वरिष्ठ साहित्यकार हिमाचल प्रदेश

मानसून का जिक्र आते ही बारिश के आनंद की अनुभूति होती है। घर के अंदर बैठे हुए बाहर खिड़कियों से रिमझिम बरसती पानी की बूंदों को निहारना और पानी में भीगने से लेकर अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए नृत्य करना किसे नहीं भाता भला ऐसे मौसम में। हां, उस पर यदि गरमागरम पकौड़े हो जाएं चटपटी चटनी के साथ तो बात ही क्या, आ गया न मुंह में भी पानी बरसात वाला, लेकिन मानसून के इस मौसम में हमें अपनी सेहत के लिए भी बड़ा सजग रहने की जरूरत होती है।

हमारे घर से बाहर होने पर मौज-मस्ती करने कहीं जाते हुए राह चलते हुए सड़क किनारे रास्ते में छोले-भटूरे, चाट-पकौड़ी और आइसक्रीम के ठेलों पर हम बड़े चाव से ऐसी चीजें खाते हैं। और यह चाट-पकौड़ी, छोले-भटूरे, टिक्की, समोसे के ठेले हमें प्राय: कहीं न कहीं दिख ही जाते हैं। अपना वाहन हो तब तो बात ही कुछ और होती है। वैसे भी जब हम बस, टैक्सी में भी सफर कर रहे हों या फिर अपने ही गांव नगर शहर में घूमने फिरने गए हों ऐसे ठेले वाले कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं।

अपने वाहन में तो कहीं भी यह चाट पकौड़ी वाले दिखते ही मुंह में लार आना स्वाभाविक होता है । और झट से हम बिना कुछ पूछताछ किए अपनी अपनी पसंद की ऐसी चीजें बेचते हुए दुकानदार को बताकर खूब चटखारे लेकर खाते हैं। अब बात आती है पैसे देने की तो हमारी चीख निकलते निकलते गले में अटक जाती है। पता है क्यों, क्योंकि हम बिना मोल भाव किए हुए अपनी मनपसंद वस्तु का स्वाद तो चख लिए होते हैं। भला अब मोल देने में चूं चपड़ कैसी।

यह ठेले वाले हमें अपने शहर, गली-मोहल्ले और बस ठहराव के साथ ही अक्सर चौराहों पर मिल जाते हैं। इनकी बनाई गई चीजों पर सेहत से संबंधित स्थानीय विभाग का कोई कड़ा शिकंजा हो प्रतीत नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में ऐसे ठेले वाले आमतौर पर हर जिला, तहसील, गांव, शहर में मिल ही जाएंगे। अधिकतर यह दूसरे रा'यों से आए लोग ही हैं जो अपने रोजगार की तलाश में हिमाचल जैसे 'समृद्ध' प्रदेश में अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए ऐसी ही खाद्य वस्तुएं बेचते हुए करते हैं। वह बड़े आराम से अपना जीवन काट रहे हैं, क्योंकि इन पर न तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन का कोई दबाव रहता होगा, कह नहीं सकता। गोलगप्पे, छोले-भटूरे, टिक्की-छोले वाले हों या फिर आइसक्रीम वाले यह खूब चूना लगाते हैं अपने खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हुए हम ग्राहकों को, क्योंकि दो टिक्की और सफेद काबुली छोले डालकर ये लोग पूरे साठ-सत्तर रुपए ऐंठ लेते हैं। ऐसे में दुकानदार और ग्राहकों में लेन देन करते हुए कहासुनी होकर बात लड़ाई झगड़े और खून खराबे तक पहुंच जाती है।

स्थानीय प्रशासन की ओर से इन फेरी विक्रेताओं की कीमतों और गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी कम ही नजर आती है। कार्रवाई होने पर भी ठेले कुछ समय बाद दूसरी जगह फिर लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाकी स्थानों की तो बात छोड़िए अपने पालमपुर की ही बात करूं तो यहां अनगिनत ठेले जहां कहीं लगे रहते हैं जो अपने खाद्य पदार्थों को अपने मन मुताबिक भाव लेकर ग्राहकों को धड़ल्ले से बेचते हैं।

ऐसे ठेले नगर निगम पालमपुर क्षेत्र के साथ लगती सीमा पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति भी ऐसी ही है, जिस पर तुरंत नियंत्रित करना बेहद आवश्यक होगा। बात जगह जगह पर अपना रोजगार फैलाने की नहीं है, बात है स्वास्थ्य और सीमित भाव की जिसे ये लोग दरकिनार किए बैठे हैं।

स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि अन्य स्थानीय बाजार भावों की ही भांति इनके खाद्य पदार्थों के बिक्री भाव भी सुनिश्चित करे। साथ ही स्थानीय और संबंधित स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर इनके खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे जिससे प्राय: मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव किए जा सकें।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> **निराशा** के समान दूसरा पाप नहीं। आशा सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है तो निराशा घोर अंधकार है।
>
> -रश्मिमाला

संपादकीय

समान अधिकारों की नई पहल

मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 का पारित होना भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। यह केवल एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि नागरिक अधिकारों की समानता सामाजिक न्याय और कानूनी व्यवस्था में एकरूपता स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की है। इससे पहले गोवा में लंबे समय से समान नागरिक कानून लागू है जबकि उत्तराखंड और असम ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही बहस को नई गति देने वाला माना जा रहा है।

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में व्यक्तिगत कानून लंबे समय से अलग अलग धार्मिक समुदायों की परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर संचालित होते रहे हैं। विवाह तलाक उत्तराधिकार गोद लेना और पारिवारिक विवादों जैसे विषयों में अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानून लागू रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय यह महसूस किया था कि भविष्य में देश को ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जहां सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू हो। इसी सोच को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के रूप में स्थान दिया गया। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश दिया गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी नहीं हैं लेकिन वे शासन की दिशा और नीति निर्माण के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को प्रभावित करना नहीं बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता का सिद्धांत तभी मजबूत माना जाता है जब कानून के सामने सभी नागरिक समान हों और व्यक्तिगत अधिकारों के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। यही कारण है कि इस विधेयक को सामाजिक सुधार और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

विधेयक में शामिल कई प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का उद्देश्य विवाह संस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी व्यवस्थाओं पर रोक लगाने से महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण भी इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे वैवाहिक संबंधों से जुड़े विवादों में पारदर्शिता आएगी और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आधुनिक समाज में बदलती सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे संबंधों को कानूनी पहचान देने और संबंधित पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को कम करने में सहायता मिल सकती है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था उपलब्ध होगी।

उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में समान अधिकार देने का प्रावधान भी इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। लंबे समय से विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं। समान नागरिक संहिता के माध्यम से इन असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो सकें। यह व्यवस्था संविधान में निहित समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप मानी जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा है। यह निर्णय उनकी सांस्कृतिक परंपराओं सामाजिक व्यवस्था और विशिष्ट पहचान के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत का संविधान देश की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है और जनजातीय समाज की विशिष्ट परंपराओं की रक्षा को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए इस वर्ग को अलग रखते हुए संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है ताकि समानता और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे। समान नागरिक संहिता पर लंबे समय से देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। इसके समर्थकों का तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कानूनी भेदभाव समाप्त हो सके।

-शिवांश धाकड़

कविता

कोई करे तो क्या करे

उदयवीर भारद्वाज
भारद्वाज भवन, मंदिर मार्ग, कांगड़ा (हि.प्र.)

कोई करे तो क्या करे, साया ही जब साथ ना दे
आता नहीं कोई जख्म सीने, अपने ही जब गहरे घाव दें
मुर्दा हुआ जब, रो-रो कर चैन से सोने न देंगे
रह गया जिंदा जीने न देंगे, उत्तर सके न दिल में
पत्थर मुझे समझने वाले, क्या बुरा किया तुम्हारा
पाल लिए क्यों वहम दिल में, हैं सब अपने
प्यार मोहब्बत से जी लो यारो,लुट गया या लुटा दिया सब मैंने
इस घड़ी पास नहीं कुछ मेरे, क्यों हुआ कैसे हुआ
समझ कुछ आता नहीं, इन्तेहा से गुजर गया अंध प्यार में
परख न सका स्वार्थ तेरे, थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही
गवा कर रिश्ते नाते सारे, क्या कहूँ
जुबां बंद है देख, बर्बादी के नजारे
कोई करे तो क्या करे, साया ही जब साथ न दे
आता नहीं कोई जख्म सीने, अपने ही जब गहरे घाव दें

कॉकरोच आंदोलन: विरोध की नई शैली और राजनीति के बदलते समीकरण

डॉ. सिंपल सुशील शर्मा
स्वतंत्र लेखक

सोशल मीडिया पर वायरल हुए व्यंग्यात्मक विरोध-प्रदर्शन ने अब तक प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहे राजनीतिक विपक्ष, विशेषकर वामपंथ के कमजोर पड़ चुके समूहों को एक नया मंच दे दिया है। किसान आंदोलन की तरह इसे भी बड़ा जनआंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आधार खोने के बाद यह उनके लिए अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता वापस पाने का एक अवसर भी बन सकता है।

इतिहास बताता है कि युवाओं के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। वे जनता की असंतुष्टि और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों का माध्यम होते हैं। लेकिन किसी भी आंदोलन को समझने के लिए यह जरूरी है कि वास्तविक जनभावनाओं, राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित अभियानों और विदेशी शक्तियों द्वारा ऐसे आंदोलनों का लाभ उठाने के प्रयासों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। आंदोलन नाम का गला घोंटने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी केजरीवाल, अरुंधति रॉय, योगेंद्र यादव जैसे लोग इस आंदोलन को अपने लिए संजीवनी जैसा बनाना चाहते हैं।

राजनीतिक अध्ययन भी यह स्वीकार करते हैं कि कई बार शक्तिशाली राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और डिजिटल प्रचार तंत्र रणनीतिक महत्व वाले देशों में अपने हितों के अनुसार माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सूचना युद्ध, साइबर अभियान, मीडिया नैरेटिव और वित्तीय सहायता जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रभावित देशों में अस्थिरता और अराजकता पैदा हो सकती है। भारत भी लंबे समय से बाहरी वित्तपोषण और विदेशी हस्तक्षेप की चुनौतियों का सामना करता रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 लागू किया गया, ताकि विदेशी धन के दुरुपयोग और अवैध हस्तक्षेप पर रोक लगाई जा सके। सोनम वांगचुक का नाम भी इस कानून से जुड़े विवादों में सामने आया है। सरकार के साथ संवाद की कोशिश सफल न होने के बाद उन्होंने वर्तमान आंदोलन का रास्ता चुना।

आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल तकनीक, रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उसकी बढ़ती भूमिका ने बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। ऐसे समय में भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिरता केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हमने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का पतन देखा, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का सत्ता से हटना देखा और नेपाल में तथाकथित 'जनरेशन ' आंदोलन भी देखा। इन सभी घटनाओं को लेकर अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषण मौजूद हैं। ऐसे समय में जब भारत 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तब बाहरी चुनौतियाँ तो स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि आंतरिक स्तर पर भी विकास की गति को बाधित करने वाले प्रयास हों, तो यह चिंता का विषय है। लोकतंत्र का अर्थ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य है, लेकिन राष्ट्रीय विकास और स्थिरता को नुकसान पहुँचाना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

ग्रामीण विकास के लिए कृषि पशुपालन और पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है

प्रो. मनोज डोगरा
राजकीय महाविद्यालय बड़सर

जनसंख्या बढ़ जाने के साथ ही हमारे देश एवं प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशु-पालन एवं बागवानी आदि का कार्य कम होने तथा पारंपरिक व्यवसाय बंद होने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार कम हुए हैं। ग्रामीणों ने भी अब पहले की तरह कड़ी मशक्कत करनी भी छोड़ दी है। इससे उनमें गर्मी व सर्दी सहन करने की भी क्षमता कम हुई है। नतीजन उन्हें कई बीमारियां भी घेरने लगी हैं।

कृषि से संबंधित कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य आधुनिक मशीनों के उपयोग में आने से भी पारंपरिक व्यावसाय न के बराबर रह गए हैं। यदि कहीं ऐसे छिटपुट व्यवसाय चल भी रहे हैं तो वह घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। जिस काम को पहले चार लोग चार दिनों में पूरा करते थे, अब मशीनों से उस काम को कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही मशीनों से होने वाला काम या उत्पाद सस्ता भी पड़ जाता है, जबकि हाथ से बनाए उत्पाद को बड़ी मुश्किल से औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है। कई बार तो ऐसे कारीगरों को काफी घाटा भी उठाना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी भारी कमी आई है। इससे लोगों के पास काम धंधा न होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है।

हालांकि, सरकार ऐसे उद्योगों के पुनरोत्थान के लिए संबंधित लोगों को वितीय मदद भी दे रही है लेकिन लोगों को ऐसा रोजगार चाहिए जिसमें प्रति माह निर्धारित धनराशि मिले ताकि आसानी से वे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित न होने से युवा वर्ग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहा है। सारा सामाजिक ढांचा नगरों-महानगरों के आसपास बिखर गया है। किसानों द्वारा खेतीबाड़ी का काम कम करने या छोड़ देने से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर उपजाऊ भूमि बंजर होने के कगार पर पहुंच गई है। उस भूमि में बड़ी मात्रा में जहरीली घास फैल गई है। इससे पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है तथा पशुचारे की भी कमी हो गई है। इसके चलते पशुपालकों ने अपने पशु भी नगर-कस्बों की ओर धकेल दिए हैं।

पहले गांव में जब व्यापक स्तर पर कृषि का काम होता था तो उसके साथ और भी कई पारंपरिक व्यवसाय थे। किसान अपनी उपज से ही उनका मेहनताना चुकाते थे। नकद पैसे का लेनदेन बहुत ही कम था। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कम ही दिखाई दे रही है। यह भी सच्चाई है कि कुछ लोगों के ढुलमुल रवैये के चलते कृषि एवं पशुपालन के व्यवसाय में बेहद कमी आई है। एक समय था जब किसान अपनी उपज से अपने परिवार के साथ ही अन्य पारंपरिक व्यवसाय करने वालों के परिवार का भी पेट पालता था।

लोहार लोहे या लकड़ी के औजार व अन्य उपकरण बनाते थे। कारीगर बांस की टोकरियां, अनाज रखने वाली बड़ी बड़ी पेड़ियां व अन्य छोटी मोटी वस्तुएं बनाते थे। खड्डों नालों के किनारे घराट चलाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जूते बनाने या उनकी मरम्मत करने वाले, बाल काटने वाले तथा ऊनी कपड़े बुनने वाले आदि व्यवसाय से जुड़े लोग अब गांव में कहीं ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूर जाना पड़ता है। अपने घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें नकद पैसे की भी जरूरत होती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

ईमानदारी से दिया गया कर बनता है देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आर्थिक पूंजी

सुभाष चंद कासव
राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
कवि लेखक एवं साहित्यकार

भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के ईमानदार करदाताओं के योगदान को सम्मान देने और नागरिकों के बीच कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2010 में आयकर विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। तब से यह दिन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि कर व्यवस्था के महत्व और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को समझने का अवसर बन गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की आर्थिक प्रगति उसकी कर प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर करती है। करों से प्राप्त धन ही सरकार को विकास योजनाओं को लागू करने और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।

भारत में आयकर व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है। आधुनिक आयकर प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1860 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन आर्थिक चुनौतियों से निपटना और सरकारी राजस्व बढ़ाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय आयकर प्रणाली में समय के साथ अनेक सुधार किए गए। बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में संशोधन हुए और कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया गया। आज आयकर विभाग आधुनिक तकनीक के माध्यम से करोड़ों करदाताओं को सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय आयकर दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों में यह समझ विकसित करना है कि कर केवल सरकार को दिया जाने वाला धन नहीं बल्कि देश के विकास में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी आय के अनुसार कर का भुगतान करती है तो वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनती है। यही राशि सड़कों के निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा व्यवस्था रेलवे हवाई अड्डों जलापूर्ति बिजली रक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च की जाती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कर का प्रत्येक रुपया देश के विकास की नींव को मजबूत करने में योगदान देता है।

भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में विकास कार्यों के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों किसानों महिलाओं युवाओं वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी अनेक पहलें कर से प्राप्त राजस्व के आधार पर संचालित होती हैं। इसलिए प्रत्येक करदाता अप्रत्यक्ष रूप से इन योजनाओं की सफलता में अपनी भूमिका निभाता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने आयकर प्रणाली को अधिक सरल पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले जहां कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जटिल मानी जाती थी वहीं अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन माध्यम से आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। आयकर रिटर्न भरना कर का भुगतान करना रिफंड की स्थिति देखना और विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करना अब डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संभव हो गया है। इससे समय की बचत हुई है और करदाताओं को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

प्रतिभा की मिसाल मृणाल ठाकुर

24 जुलाई 1992 को महाराष्ट्र के धुले में जन्मी मृणाल ठाकुर आज भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की और अपनी मेहनत तथा लगन के दम पर बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अलग पहचान बनाई। बचपन से ही अभिनय में रुचि रखने वाली मृणाल ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया और हर चुनौती का साहस के साथ सामना किया।

मृणाल ठाकुर
जन्म : 24 जुलाई 1992

मृणाल ठाकुर ने सबसे पहले टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया। धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाए गए उनके किरदार ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे की ओर कदम बढ़ाया और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों तथा समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया। उनकी पहली चर्चित हिंदी फिल्मों में लव सोनिया शामिल रही जिसमें उन्होंने एक बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके संवेदनशील अभिनय की काफी सराहना हुई।

इसके बाद मृणाल ने सुपर 30 में अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ काम किया। फिल्म में उनके सहज और प्रभावशाली अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद तूफान में उन्होंने फरहान अख्तर के साथ अभिनय किया और एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। वर्ष 2022 में प्रदर्शित तेलुगु फिल्म सीता रामम ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में निभाए गए सीता महालक्ष्मी के किरदार ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद हाय नन्ना में भी उनके अभिनय की व्यापक प्रशंसा हुई और उन्होंने दक्षिण भारतीय दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान स्थापित की।

मृणाल ठाकुर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हर भूमिका में पूरी तरह ढल जाती हैं। चाहे भावनात्मक दृश्य हों या गंभीर किरदार उनकी अभिव्यक्ति और संवाद अदायगी दर्शकों को प्रभावित करती है। वह अपनी सादगी विनम्रता और पेशेवर व्यवहार के लिए भी जानी जाती हैं।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

देवरिया के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लगाए जाएंगे सोलर पैनल

एजेंसी, देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की प्रधानाचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में सोलर प्लांट स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि सोलर प्लांट स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन और संबंधित विभाग नेडा को भेजें। स्वीकृति मिलने के बाद विद्यालयों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट लगने से विद्यालयों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे छात्राओं की पढ़ाई और अन्य गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष की सजा 24 हजार रुपए का जुर्माना

एजेंसी, देवरिया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के प्रयास के पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई। मामला बरहज थाने में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। आरोपी शम्मी अंसारी उर्फ सोनू निवासी कपरवार नौका टोला के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया की अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने सात साल की सजा के साथ 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने इसे अभियान की बड़ी सफलता बताया।

एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास : मनीष शुक्ला

एजेंसी, लखनऊ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर स्वच्छ, हराभरा और स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सकता है। गुरुवार को गोमती नगर में शास्त्रार्थ फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मनीष शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू यह अभियान पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर हवन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान राजीव रंजन सिंह, जाह्नवी सिंह, आशीष जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।

दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर बागपत में हाई अलर्ट, टोल प्लाजा पर हो रही चेकिंग

एजेंसी, बागपत। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए बागपत पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी सूरज कुमार राय के निर्देश पर जिलेभर में अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली जाने वाले सभी मार्गों और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित मवीकलां टोल प्लाजा पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रख रही है। खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी बनाए हुए है। भ्रामक या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मैट्रिक्स ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था लगातार जारी रहेगी।

संसद में चर्चा से भाग रहा विपक्ष, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार : पंकज चौधरी

परीक्षा मामलों में उठाए गए कदमों का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया जिक्र

एजेंसी, लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार संसद में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर भागकर सड़क को राजनीति का मंच बना रहा है। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां चर्चा और संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

राजधानी स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पंकज चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में चर्चा करने के बजाय धरना प्रदर्शन करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को सड़क पर उठा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि

प्रधानमंत्री आवास केवल किसी व्यक्ति का निवास नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इस तरह का प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के साथ बातचीत के लिए अपने मंत्रियों को भेजा था, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसे संसद के भीतर उठाना चाहिए। सरकार हर विषय पर चर्चा करने और तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है।

उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। जिन मामलों में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, वहां दोबारा परीक्षाओं का आयोजन कर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की गई। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों और युवाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन जरूरी है। विपक्ष को सदन में आकर रचनात्मक चर्चा करनी चाहिए, ताकि देशहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बेहतर निर्णय लिए जा सकें। पंकज चौधरी ने विपक्ष से अपील की कि वह सड़क पर प्रदर्शन करने के बजाय संसद में अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

संत रविदास की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी भाजपा

एजेंसी, लखनऊ

संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई से होगी। इसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में सामूहिक आरती, सत्संग और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के माध्यम से संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेशभर में आयोजित होंगी आरती और गोष्ठियां

अभियान की तैयारियों को लेकर गुरुवार को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी और अनुसूचित मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रमों के संचालन को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने अभियान से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। भाजपा प्रदेश मंत्री राहुल वाल्मीकि ने कहा कि वर्तमान समय में जब कुछ शक्तियां समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में संत रविदास के विचार समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संदेशों को अपनाकर सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत किया जा सकता है।

कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका रावत, बृज बहादुर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यशाला में भाजपा नेताओं ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक एकता और समानता का मार्ग दिखाते हैं। अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने और समरसता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

सात करोड़ से बदलेगी जरगो जलाशय की तस्वीर

एजेंसी, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले के अहरौरा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जरगो जलाशय की सूरत जल्द बदलने वाली है। सिंचाई विभाग की ओर से करीब सात करोड़ रुपये की लागत से जलाशय के बांध की मरम्मत और मजबूती का कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत क्षतिग्रस्त पिचिंग को हटाकर नई पत्थर पिचिंग टॉप लेवल तक लगाई जा रही है।

ऐतिहासिक जरगो जलाशय की मरम्मत से बढ़ेगी सिंचाई व्यवस्था की सुरक्षा

विभाग के अनुसार, बांध की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगभग छह किलोमीटर लंबे क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। इसके लिए पांच वॉच टॉवर बनाए जाएंगे, जिससे बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके।

जरगो जलाशय का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1956 से 1958 के बीच सात नदियों और 27 नालों को बांधकर किया गया था। उस समय इस परियोजना पर करीब एक करोड़ 21 लाख रुपये खर्च हुए थे।

घाघरा नदी की स्थिति पर नजर राहत संसाधन तैयार रखने के निर्देश

एजेंसी, बाराबंकी। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाराबंकी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को उपजिलाधिकारी आकांक्षा गुप्ता ने तहसील क्षेत्र के तटवर्ती गांव तपेसिपाह पहुंचकर बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने नदी किनारे कटान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जलस्तर की प्रत्येक घंटे रिपोर्ट कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा। एसडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत कर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए नाव, लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी और अन्य जरूरी संसाधन तैयार रखे गए हैं।

जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन से संबंधित घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग

एजेंसी, वाराणसी

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन, संसद मार्च और उससे जुड़े घटनाक्रम की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने गुरुवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मामले की समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की मांग की।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र संयोजक एवं दि बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि वह 17 जुलाई 2026 से इस मामले को लेकर सक्षम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ज्ञापन में अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने और संसद की सुरक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आयोजकों, सहयोगियों और संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की।

आलू का न्यूनतम दाम तय करने की मांग को लेकर हाथरस में किसानों ने शुरू किया अनशन

एजेंसी, हाथरस

आलू की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने और किसान विरोधी कानूनों के विरोध में हाथरस में किसानों ने अनशन शुरू कर दिया है। किसान कृष्णा खोकिया, अमित चौधरी और इंद्रजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। किसानों ने बुधवार शाम से अनशन शुरू किया।

फसल घाटे से परेशान किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन

किसान कृष्णा खोकिया ने बताया कि आलू की फसल के लगातार कम दाम मिलने से किसानों की लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज लेकर फसल तैयार करते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि अच्छी कीमत मिलने से वे कर्ज चुका सकेंगे, लेकिन बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद आलू के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से गेहूं, बाजरा और मक्का की तर्ज पर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य लागू होने से उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और बाजार में बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

इसके अलावा किसानों ने किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई। अनशन पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने प्रशासन और सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है।

पांच लाख की जमीन, मिले सिर्फ 40 हजार; युवक ने एसपी से मांगा न्याय

एजेंसी, महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जमीन बिक्री के बाद बकाया रकम मांगने पर युवक के साथ कथित रूप से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अजनर थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव निवासी कालूराम कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय नाथूराम ने बताया कि उसने अपनी थुरट मौजा स्थित जमीन को जरूरत के चलते बेलाताल कस्बा निवासी दिनेश चौरसिया के साथ पांच लाख रुपये में बेचने का इकरारनामा किया था। यह समझौता 16 अप्रैल 2024 को हुआ था। पीड़ित के अनुसार, इकरारनामे के समय खरीदार ने केवल 40 हजार रुपये दिए थे।

कालूराम ने बताया कि रजिस्ट्री के समय खरीदार ने खाते में पैसे नहीं होने की बात कहते हुए नकद भुगतान करने का भरोसा दिया। विश्वास के आधार पर उसने 16 जून 2026 को जमीन की रजिस्ट्री कर दी। आरोप है कि 29 जून को जब उसने शेष रकम मांगी तो उसके साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिससे उसे और उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। एसपी ने शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जमीन की पूरी रकम नहीं मिलने के बावजूद रजिस्ट्री कराई गई। अब बकाया धनराशि मांगने पर उसे धमकाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना पुलिस को जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शराब के नशे में हुआ झगड़ा बना मौत का कारण, दोस्त हिरासत में

एजेंसी, नोएडा

उत्तर प्रदेश के नोएडा में शराब पीने के बाद दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद एक युवक की मौत का कारण बन गया। थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के शाहपुर गांव में बुधवार रात दो दोस्तों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक जमीन पर गिर गया और उसका सिर पास पड़े पत्थर से टकरा गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, शाहपुर गांव निवासी शिशुपाल पुत्र मक्खन और उसका साथी टीटू बुधवार रात एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि टीटू ने शिशुपाल को धक्का दे दिया, जिससे वह असंतुलित होकर पास पड़े पत्थर पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद शिशुपाल को उसके साथियों ने भंगेल गांव स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सोमनेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी टीटू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद का सामने आया है। आरोपी से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

छात्रों के मुद्दों पर विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार : सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम

एजेंसी, झांसी

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ हुए कथित व्यवहार को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है और कई छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के सभी फैसलों को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और सरकार से पारदर्शी व्यवस्था की मांग की।

विकास

एम्स, मेडिकल कॉलेज और सड़क परियोजनाओं का जिक्र कर योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

995 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी गोरखपुर की तस्वीर: मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर को 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। टीपी नगर-पैडलेगंज मार्ग स्थित समारोह में मुख्यमंत्री ने जिले के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने दस नई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बदलाव का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर राजनीतिक निशाना साधा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे, वही आज आस्था के सबसे बड़े समर्थक बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से आस्था की बातें सुनना जनता को हास्यास्पद लगता है। उन्होंने

आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान रामभक्तों के साथ अन्याय किया, जबकि कांग्रेस ने मंदिर आंदोलन और भगवान श्रीराम के अस्तित्व को लेकर न्यायालय में अपना पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि ऐसे दलों को अब आस्था पर उपदेश देने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध और अराजकता से होती थी। धार्मिक आयोजनों के दौरान तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आती थीं। व्यापारी, महिलाएं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। आज लोग बिना डर के अपना व्यापार और दैनिक जीवन चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की स्वास्थ्य व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से हजारों बच्चों की मौत होती थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई और पूर्वांचल को इंसेफेलाइटिस के संकट से लगभग मुक्त कराने का काम किया।

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियों में पक्षपात होता था और योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिलते थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्षों में बिना भेदभाव लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा निजी निवेश के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना से युवाओं और कारीगरों को स्वरोजगार का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय यह शहर अपराध, माफिया और अव्यवस्थाओं के कारण जाना जाता था। निवेशक यहां आने से बचते थे, लेकिन अब बेहतर कानून व्यवस्था और सुविधाओं के कारण गीडा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है।

एनसीसी कैडेट्स ने कैंप में किया अनुशासन व समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन : रितु श्रीवास्तव रावत

एजेंसी, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित 10 दिवसीय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। 15 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित इस शिविर में कैडेट्स ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। समापन समारोह में कैडेट्स की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की गई।

कैडेट्स को मिला प्रशिक्षण और नेतृत्व का अनुभव

युवाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में एनसीसी प्रशिक्षण बना सहायक

समारोह को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट एवं कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितु श्रीवास्तव रावत ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण युवाओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कैडेट्स से एनसीसी के आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' को जीवन में अपनाने और पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ देश सेवा के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करना है।

उन्होंने कैडेट्स को आगामी आईजीसी टीएसासी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट टीम में चयन के लिए बेहतर प्रदर्शन करने को प्रेरित किया। दस दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स ने ड्रिल, हथियार संचालन, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, शारीरिक प्रशिक्षण और विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भी कैडेट्स ने उत्साह दिखाया।

रक्षा मंत्रालय, प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी एवं प्रवक्ता विंग कमांडर देबार्थो धर ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का काम करते हैं। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स और विजेता टीमों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कैडेट्स की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक फोटो, धन्यवाद ज्ञापन और 'भारत माता की जय' व '15 बीएन की जय' के नारों के साथ हुआ।

ग्रामीणों के 30 लाख योगदान से संवरा सरकारी स्कूल, बेटियों की पढ़ाई बनी पूरे क्षेत्र की पहचान

सरकारी स्कूल पर बढ़ा भरोसा, पुलिस और सेना में पहुंचे 300 से अधिक पूर्व छात्र

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल

हरियाणा के कैथल जिले के सौंगरी और गुलियाणा गांवों ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। यहां ग्रामीणों ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा के माध्यम से इसे धरातल पर उतारने का काम किया है। इन गांवों में बेटियों की शिक्षा को लेकर लोगों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

यही कारण है कि अब अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सौंगरी गुलियाणा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विकास के लिए ग्रामीणों ने मिलकर 30 लाख रुपये से अधिक का योगदान दिया है। ग्रामीणों की इस पहल से स्कूल में सुविधाओं का विस्तार हुआ और विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

सौंगरी-गुलियाणा की कहानी, बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की निशानी

पांच वर्ष पहले जहां विद्यालय में कुल 294 विद्यार्थी पढ़ते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 651 तक पहुंच गई है। विद्यालय में छात्राओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है। वर्तमान में स्कूल में छात्राओं की संख्या करीब 55 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि बेटियों को बेहतर शिक्षा देने से ही उनका भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ गांवों के लोगों ने स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दिया। इन गांवों में लिंगानुपात में भी सुधार देखने को मिला है। ग्रामीणों ने बेटियों के जन्म और शिक्षा को लेकर सकारात्मक सोच अपनाई है। लोगों का मानना है कि शिक्षित बेटियां परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी बदलाव के कारण आज सौंगरी और गुलियाणा गांव शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

जहां बेटियों को मिला सम्मान वहां शिक्षा ने बदली पहचान

इस सरकारी स्कूल की उपलब्धियां भी ग्रामीणों के विश्वास को मजबूत करती हैं। यहां से पढ़ाई करने वाले 300 से अधिक विद्यार्थी पुलिस और सेना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे वर्तमान विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। ग्रामीणों की पहल से स्कूल में शिक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। और बच्चों की सफलता में ग्रामीणों का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

फतेहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में सौंपा ज्ञापन

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी फतेहाबाद ने लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रदर्शन में फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लांखेड़ा, कृष्णा पूनियां सहित जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर सरकार ने लाठीचार्ज कराया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है और युवाओं की आवाज को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने मांग की कि परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सामने आ रही समस्याओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके अलावा भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग भी की गई। कांग्रेस नेताओं ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई रोकने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

न्यूज ब्रीफ

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन नंद लाल शर्मा का निधन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन नंद लाल शर्मा का गुरुवार सुबह पंचकूला में निधन हो गया। वह 19 जुलाई से ब्रेन स्ट्रोक के कारण एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन थे। नंद लाल शर्मा ने 2 फरवरी 2024 को एचईआरसी के अध्यक्ष का पद संभाला था। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले शर्मा इससे पहले एसजेवीएन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में छह वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से अपना करियर शुरू किया और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ऊर्जा क्षेत्र और प्रशासन में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।

करनाल जिला परिषद चेयरपर्सन प्रवेश राणा की कुर्सी गई, अविश्वास प्रस्ताव पास

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। जिला परिषद की चेयरपर्सन प्रवेश राणा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को पास हो गया। जिला परिषद कार्यालय में उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की मौजूदगी में फ्लोर टेस्ट कराया गया, जिसमें प्रवेश राणा के खिलाफ 17 सदस्यों ने मतदान किया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी चेयरपर्सन पद से छुट्टी हो गई। अब जिला परिषद की जिम्मेदारी वाइस चेयरपर्सन को सौंपी गई है। इस घटनाक्रम को करनाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चेयरपर्सन के खिलाफ असंतोष चल रहा था। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कस्टोडियल टॉर्चर मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, डीजीपी से रिपोर्ट तलब

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

आरोपी ने पुलिस पर टांग तोड़ने का आरोप लगाया

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने गुरुग्राम के सोहना में पुलिस हिरासत के दौरान एक आरोपी के साथ कथित मारपीट और उसकी टांग टूटने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मामला उस समय चर्चा में आया जब आरोपी ने दावा किया कि उसकी टांग फ्लाईओवर से गिरने के कारण नहीं टूटी, बल्कि पुलिस हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी के अनुसार पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इन आरोपों के सामने आने के बाद मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया। आयोग ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर कराई जाए और निर्धारित समय के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सिरसा पुलिस ने पकड़े दो हेरोइन तस्कर, लाखों का नशा बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिमांशु और राजपाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सीआईए ऐलनाबाद की टीम गश्त एवं चेकिंग के दौरान सिरसा शहर के मोचियांवाली गली क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर वापस मुड़कर जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। वहीं एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गांव बेगू क्षेत्र से सिरसा निवासी राजपाल को सात ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

केएमपी एक्सप्रेसवे साइट रद्द, अब जाट जोशी में बनेगा सोनीपत का आधुनिक बस अड्डा

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

हरियाणा के सोनीपत में नए बस अड्डे के निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने नए बस अड्डे के निर्माण के लिए पहले प्रस्तावित केएमपी एक्सप्रेसवे के पास की साइट को रद्द कर दिया है। अब यह बस अड्डा गांव जाट जोशी की पूर्व निर्धारित साइट पर ही बनाया जाएगा। इस फैसले से स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नए बस अड्डे को लेकर विधायक निखिल मदान ने चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजशेखर वुंडरू और परिवहन विभाग के निदेशक वीरेंद्र दहिया से मुलाकात कर जाट जोशी स्थित पुरानी साइट पर ही निर्माण कराने की मांग रखी। बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इससे पहले परिवहन विभाग की ओर से नया बस अड्डा केएमपी एक्सप्रेसवे के निकट बनाने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इस निर्णय को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठाए गए थे। लोगों का कहना था कि शहर से अधिक दूरी होने के कारण यात्रियों को बस अड्डे तक पहुंचने में अतिरिक्त समय और खर्च उठाना पड़ेगा। इसी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने पुरानी साइट को बहाल करने की मांग की थी।

सरकार के नए निर्णय के बाद अब डीआईएमटीएस (डीएमआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परामर्श एजेंसी) को जाट जोशी स्थित साइट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

65 साल पुराने राम मंदिर में बवाल, एडवोकेट पर तानी पिस्टल; कपड़े फाड़ने का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर के एक 65 साल पुराने राम मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ लोग मंदिर परिसर में पहुंचे और वहां पाठ कर रहे एडवोकेट व उनके साथियों के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और कपड़े फाड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धक्का-मुक्की और मारपीट दिखाई दे रही है। पीड़ित ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को बाहर फेंकने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

नारनौल एनकाउंटर के बाद बदमाश का प्लास्टर ड्रामा, कोर्ट पहुंचते ही खुला राज

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। नारनौल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए इनामी बदमाश को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोपी ने पहाड़ी से गिरने के कारण पैर में फ्रैक्चर होने की बात बताई थी। इसके बाद उसे प्लास्टर लगाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां वह पुलिसकर्मियों के कंधे के सहारे पहुंचा। हालांकि, कुछ दिन बाद आरोपी सामान्य रूप से चलता दिखाई दिया, जिसके बाद उसके इलाज और चोट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की मेडिकल जांच और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है।

हरियाणा के 15 हजार क्लर्कों को बड़ी राहत बेसिक वेतन में जुड़ेंगी अतिरिक्त वेतनवृद्धि

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य के लगभग 15 हजार लिपिकों (क्लर्कों) को बड़ी राहत देते हुए उनकी अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को मूल वेतन (बेसिक पे) में स्थायी रूप से शामिल करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के बाद संबंधित कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाले सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर मिलेंगे। यह आदेश 8 फरवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर अब सभी वित्तीय और सेवा लाभ दिए जाएंगे।

वित्त विभाग ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शंकाओं का समाधान करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने साफ किया है कि लिपिकों को दी गई अतिरिक्त वेतन वृद्धि केवल अस्थायी लाभ नहीं होगी, बल्कि इसे उनके बेसिक वेतन का स्थायी हिस्सा माना जाएगा। इस फैसले का लाभ लिपिकों के अलावा वरिष्ठ लिपिकों, सहायकों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को भी मिलेगा।

अब वेतन निर्धारण, एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी), पदोन्नति, पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य वित्तीय लाभ बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर तय किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों की भविष्य की आय और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार के आदेश के अनुसार वरिष्ठ लिपिकों को मिलने वाली तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा वर्ष 2020 बैच के लिपिकों को मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी उनके वर्तमान मूल वेतन में स्थायी रूप से जोड़ दी जाएंगी। इससे वेतन संबंधी कई लंबित विवाद और भ्रम समाप्त होने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

उनका कहना है कि इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वेतन से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। वहीं, वित्त विभाग का मानना है कि इस आदेश के बाद कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और सेवा लाभों से जुड़े अधिकांश विवाद समाप्त हो जाएंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के साथ भविष्य में भी वेतन और सेवा संबंधी लाभों में भी स्थिरता आएगी।

हांसी जिम ट्रेनर हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

हरियाणा के हांसी में चर्चित कपिल रेड्डू हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिम ट्रेनर और रेड जिम संचालक कपिल रेड्डू की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता रोहित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। देर रात गांव पुठी मंगल खां के पास सीआईए 2 की टीम और आरोपी रोहित के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी रोहित हत्या मामले में वांछित चल रहा था। सूचना मिलने के बाद सीआईए-2 की टीम ने इंस्पेक्टर कसान सिंह के नेतृत्व में उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी ने कथित रूप से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आगे इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस वाहन पर भी गोली लगने की सूचना सामने आई है। हालांकि, इस दौरान किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।

जांच में सामने आया है कि रोहित पर कपिल रेड्डू हत्याकांड में हथियार उपलब्ध कराने और वारदात की रेकी करने का आरोप है। पुलिस पहले ही इस मामले में दो अन्य आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या की साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच आगे जारी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद कपिल रेड्डू हत्याकांड में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपी रोहित से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश, हथियारों की व्यवस्था और वारदात में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है।

पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को बड़ा मौका, मिलेगा उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल और व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में पंचकूला में राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र युवाओं को इस योजना से जोड़ना है।

कार्यशाला में बताया गया कि 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को देश की 2,000 अग्रणी कंपनियों में छह से नौ माह की इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने

हरियाणा के युवाओं को 2000 कंपनियों में इंटर्नशिप, हर माह नौ हजार रुपए

कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों में वास्तविक कार्य अनुभव उपलब्ध कराना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे पात्र विद्यार्थियों और हाल ही में पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करें। इससे अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके कौशल का विकास होगा और भविष्य में बेहतर रोजगार मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उद्योगों की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अनुभव उन्हें प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगा। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों और शिक्षण संस्थानों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है, ताकि पात्र युवा समय पर पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठा सकें। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना हरियाणा के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समोसे के भाव में सफर, फिर भी खाली दौड़ रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

पर्यावरण अनुकूल तकनीक से लैस हाइड्रोजन ट्रेन अभी यात्रियों की पहली पसंद बनने के लिए कर रही संघर्ष

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आधुनिक रेल तकनीक की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम मानी जा रही है। पर्यावरण के अनुकूल ईंधन, अत्याधुनिक सुविधाओं और अपेक्षाकृत कम किराए जैसी खूबियों के बावजूद यह ट्रेन अभी यात्रियों की पहली पसंद नहीं बन सकी है। जींद-सोनीपत रेलखंड पर शुरू की गई इस विशेष ट्रेन में शुरुआती दिनों में अपेक्षा से कम यात्री सफर कर रहे हैं। हालांकि पहले दिन की तुलना में यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन रेलवे की उम्मीदों के अनुरूप भीड़ अब तक नहीं जुट पाई है।

ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार सुबह 7:40 बजे जींद रेलवे जंक्शन से रवाना हुई। संचालन के चौथे दिन भी ट्रेन समय पर चली और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके बावजूद अधिकांश कोचों में सीटें खाली नजर आईं। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि नई सेवा होने के कारण लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी मिलने और नियमित संचालन के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम यात्रियों की सबसे बड़ी वजह इस रूट पर पहले से उपलब्ध वैकल्पिक परिवहन साधन हैं। जींद से सोनीपत और दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए कई लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनें पहले से संचालित हो रही हैं।

इन ट्रेनों का किराया 30 से 45 रुपये के बीच है और इनमें से कई ट्रेनें सीधे दिल्ली तक जाती हैं। इसके विपरीत हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल केवल जींद से सोनीपत के बीच ही संचालित हो रही है। ऐसे में दिल्ली या उससे आगे जाने वाले अधिकांश यात्री बिना ट्रेन बदलने वाली सीधी लोकल सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि यदि हाइड्रोजन ट्रेन का विस्तार दिल्ली तक किया जाए या अन्य प्रमुख स्टेशनों से जोड़ा जाए तो इसका उपयोग बढ़ सकता है। फिलहाल सोनीपत पहुंचने के बाद आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन या अन्य साधन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय और सुविधा दोनों प्रभावित होते हैं।

रेलवे का उद्देश्य इस ट्रेन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें डीजल ट्रेनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। इनके संचालन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और प्रदूषण भी कम होता है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे भविष्य में इस तकनीक का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक कोच, आरामदायक सीटें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुगम यात्रा अनुभव इसे सामान्य ट्रेनों से अलग बनाते हैं। ट्रेन की कुल

लोकल और मेमू ट्रेनों की टक्कर में पिछड़ रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन।

यात्री क्षमता लगभग 2,700 बताई जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग एक साथ सफर कर सकते हैं।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि समय के साथ लोगों में इस ट्रेन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा। यदि रूट का विस्तार किया जाता है, अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और प्रचार-प्रसार को बढ़ाया जाता है, तो यह सेवा अधिक लोकप्रिय हो सकती है। फिलहाल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक तो बन गई है, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ाना रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की प्रतिक्रिया और यात्रा संबंधी आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर समय-सारिणी, ठहराव और रूट विस्तार जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अधिकतम लाभ यात्रियों तक पहुंच सके।

यमुना किनारे गांवों में पहुंचे उपायुक्त, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल

यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने यमुना नदी से सटे कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने पलवल से मोहना ब्रिज तक राजपुर, दोस्तपुर, चांदहट, मोहबलीपुर, इंदिरा नगर, गुरवाड़ी और रहीमपुर पुल सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी किनारे बने तटबंधों, जलभराव की आशंका वाले इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को देखा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

डॉ. छिल्लर ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। उन्होंने सिंचाई, राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित प्रभावित गांवों में राहत और बचाव से जुड़े सभी संसाधन पहले से उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत दल, नाव, मशीनरी, दवाइयां, पेयजल और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आपात स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

यमुना किनारे गांवों में प्रशासन की निगरानी

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना।

उन्होंने गांव के सरपंच राजेश कुमार से क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को 24 घंटे सतर्क रहने और नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी रखने का दावा किया है। प्रशासन ने यमुना किनारे बसे गांवों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जाए और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

न्यूज ब्रीफ

सरकारी गारंटी के साथ निवेश, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना बनी पसंद

एजेंसी ,नई दिल्ली सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न की तलाश करने वाले लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय बचत टाइम डिपॉजिट (टीडी) योजना एक भरोसेमंद विकल्प बन रही है। सरकार द्वारा समर्थित इस योजना में निवेशकों की राशि सुरक्षित रहती है और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट योजना में निवेश करने वाले लोगों को बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं रहती। यही कारण है कि कम जोखिम के साथ बेहतर बचत की इच्छा रखने वाले निवेशक इस योजना को पसंद कर रहे हैं। इस योजना में अलग-अलग अवधि के लिए निवेश का विकल्प उपलब्ध होता है, जिससे लोग अपनी जरूरत और वित्तीय योजना के अनुसार धन जमा कर सकते हैं। डाक विभाग की यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है, जो सुरक्षित तरीके से अपनी बचत बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोग बैंक और अन्य निवेश विकल्पों के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसकी सरकारी सुरक्षा और निश्चित ब्याज दर इसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय बना रही है।

करोड़ों की जमीन विवाद में धोखाधड़ी का मामला, फरुखनगर पुलिस ने शुरू की जांच

एजेंसी, नई दिल्ली फरुखनगर कस्बे में तहसील के समीप स्थित 172 कनाल 12 मरला जमीन में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस मामले में करोड़ों रुपये की जमीन को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर-5 निवासी धर्मेंद्र कुमार, सुरेश और दिनेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों, रिकॉर्ड तथा अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

फरीदाबाद में किसानों का भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन, लागू न करने की मांग

एजेंसी, नई दिल्ली । फरीदाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने इस समझौते को किसान, मजदूर और लघु उद्योगों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे लागू न करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी दबाव में आकर ऐसा समझौता कर रही है, जिससे देश के किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान हो सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा है और नए समझौतों से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और लघु उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान और उचित नीतिगत फैसलों की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने कहा कि व्यापार समझौते से कृषि और छोटे उद्योगों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की।

नीट पेपर लीक मामले में दो आरोपियों की जमानत पर आज होगा फैसला

सीबीआई ने पेपर लीक मामले में गंभीर आरोप लगाए, मोबाइल से मिले प्रश्न और रिश्वत के सबूत अदालत में रखे

एजेंसी, नई दिल्ली

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपित डॉ. मनोज भगवानराव शिरूरे और शिवराज मोटेगांवकर की जमानत याचिकाओं पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए इसे देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अदालत को बताया कि यह मामला केवल प्रश्नपत्र लीक होने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि आरोपितों की भूमिका पेपर लीक करने और उसे आगे पहुंचाने की साजिश में सामने आई है।

सीबीआइ के अनुसार, जांच के दौरान आरोपित शिवराज मोटेगांवकर के मोबाइल फोन से 36 तस्वीरें बरामद की गईं। इन तस्वीरों में रसायन विज्ञान विषय के 132 हाथ से लिखे प्रश्न मौजूद थे। जांच में इनमें से 111 प्रश्न राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मास्टर प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। एजेंसी ने अदालत को बताया कि यह समानता पेपर लीक की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में शामिल है।

जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआइ का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने दावा किया कि लीक हुए प्रश्न एनटीए के पेपर-सेटिंग पैनल से जुड़े पीवी कुलकर्णी के माध्यम से बाहर आए थे। एजेंसी के मुताबिक, शिवराज ने इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपने हाथ से नोट्स तैयार किए थे। मोबाइल डाटा की जांच में सामने आया कि इन नोट्स की तस्वीरें परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले ली गई थीं।

सीबीआइ ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक जांच में बरामद नोट्स शिवराज मोटेगांवकर की ही लिखावट में पाए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने दावा किया कि लीक प्रश्नपत्र हासिल करने के लिए दी गई पांच लाख रुपये की रिश्वत की रकम दूसरे आरोपित डॉ. मनोज भगवानराव शिरूरे के ठिकाने से बरामद की गई है।

सीबीआइ ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटना से परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई और लाखों छात्रों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह की घटनाएं देश की प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर करती हैं।

न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जिला न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार करें।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने हाईकोर्ट के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और जल्द निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट के बीच न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने पर सहमति बनती है तो इसे लागू किया जा सकता है। वहीं, जो राज्य या हाईकोर्ट पहले से ही उम्र सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं, उन्हें विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल सहमति पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अदालत ने कहा कि जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था है।

ग्रामीण विकास को रफ्तार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बनाएगा सुविधाओं से लैस सामुदायिक केंद्र

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों में भी आवासीय सेक्टरों की तर्ज पर आधुनिक सामुदायिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को शादी, जागरण, पंचायत बैठक और अन्य बड़े आयोजनों के लिए शहर या सेक्टरों पर निर्भरता से राहत दिलाना है। प्राधिकरण ने पहले चरण में चार प्रमुख गांवों का चयन किया है। इनमें डाढ़ा, सिरसा, लुक्सर और इमलियाका गांव शामिल हैं। इन गांवों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों में ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्थान मिल सकेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें शहरों जैसी सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही मिल सकेंगी। सामुदायिक केंद्र सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयोगी साबित होंगे। अधिकारियों ने बताया कि चयनित गांवों में निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। योजना के सफल होने के बाद अन्य गांवों में भी ऐसे केंद्र विकसित करने पर विचार किया जाएगा।

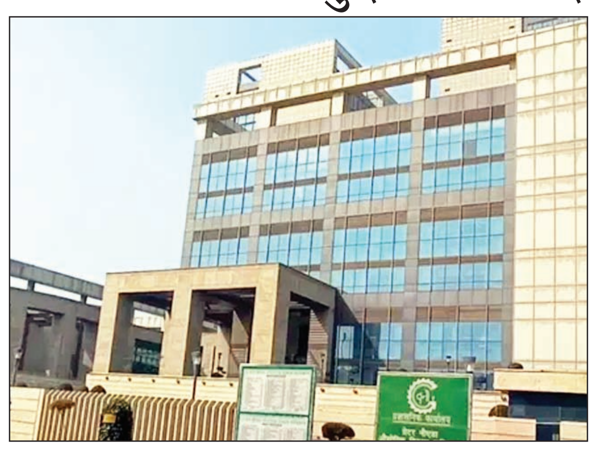

प्राधिकरण की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की योजना से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर आयोजन स्थल मिलेंगे और शहरों पर निर्भरता कम होगी।

प्रयागराज मंडल के 16 स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, आधुनिक खानपान स्टॉल होंगे स्थापित

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक खानपान और मल्टी-परपस स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इन स्टॉलों की स्थापना ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही बेहतर गुणवत्ता वाली खानपान सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान आसानी से उपलब्ध कराना है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान जरूरी वस्तुओं के लिए इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनका समय भी बचेगा।

प्रयागराज मंडल के अधिकारियों के अनुसार, इन स्टॉलों में यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आधुनिक व्यवस्था के तहत यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिल सकेंगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

16 रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी आधुनिक यात्री सुविधाएं

स्टेशन परिसर में सुविधाओं के विस्तार से यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक माहौल मिलेगा। एनसीआर लगातार स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं में भी सुधार आएगा। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को स्टेशन पर ही खानपान और जरूरी सामान उपलब्ध होगा। इससे सफर आसान होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रयागराज मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर शुरू होने वाली यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगी। आधुनिक स्टॉलों के जरिए साफ-सुथरी खानपान सामग्री और आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी।

फरीदाबाद तहसील में रोज आते हैं हजारों लोग फिर भी नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं

एजेंसी, नई दिल्ली

फरीदाबाद की सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाली तहसील में आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में संचालित तहसील कार्यालय में प्रतिदिन हजारों लोग अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है।

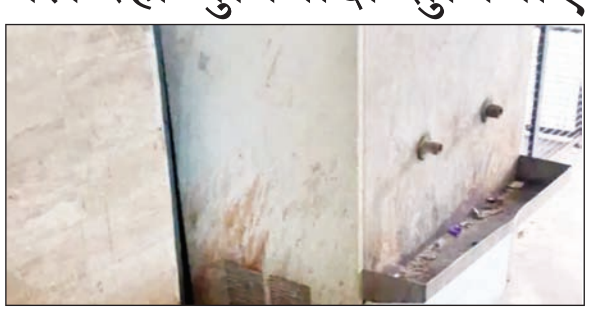

ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था न होना और शौचालयों की खराब स्थिति उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद तहसील सरकार के खजाने में सबसे अधिक राजस्व देने वाली तहसीलों में शामिल है, बावजूद इसके यहां आने वाले नागरिकों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आगंतुकों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जाए और शौचालयों की नियमित सफाई व रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। लोगों का कहना है कि जिस कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचते हैं, वहां बुनियादी सुविधाओं का होना जरूरी है। प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लोगों को राहत दी जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तहसील कार्यालय में सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें काफी असुविधा होती है।

कई बार काम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पानी और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं होने से परेशानी बढ़ जाती है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर कार्यालय परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

आजमगढ़ में दो बहनों से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के बहाने दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म तथा तीसरी बहन से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी महफूज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त गहनी खुर्द गांव का निवासी है और उसके पिता का नाम अबूबकर है। पीड़िता द्वारा 22 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। आरोपों के अनुसार, महफूज पिछले चार-पांच वर्षों से इस परिवार का विश्वास जीतकर लगातार महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहा था। वह परिजनों को डराने के लिए तांत्रिक विद्या के जरिए जान से मारने की धमकियां भी देता था, जिससे पीड़ित पक्ष डर के साये में चुप्पी साधे रहा। घटना वाले दिन आरोपी ने झाड़-फूंक के नाम पर ढोंग रचा। उसने पीड़िता के माता-पिता को बहला-फुसलाकर घर के बाहर बैठा दिया और खुद घर के अंदर जाकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

दिल्ली में बढ़े तनाव का असर मेरठ में भी, पुलिस ने टोल प्लाजा और प्रमुख मार्गों पर बढ़ाई निगरानी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में संसद मार्च और सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खुफिया विभाग से मिले अलर्ट के बाद मेरठ पुलिस ने बुधवार रात जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस ने काशी टोल प्लाजा और मोहिउद्दीनपुर पुलिस चौकी पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। खुफिया सूचना मिली थी कि मेरठ के रास्ते कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वहां की स्थिति प्रभावित होने की आशंका है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया और दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी।

चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने टोल और चौकियों से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वाहनों और यात्रियों की जानकारी भी जुटाई गई। जांच पूरी होने के बाद ही वाहनों को दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह अभियान अभी कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। जिले के प्रमुख प्रवेश और निकासी मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जा रही है।

मेरठ में अलर्ट, दिल्ली मार्गों पर पुलिस की सख्त चेकिंग

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मेरठ पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध गतिविधियों की जांच तेज कर दी है। दिल्ली में बढ़े तनाव के बाद मेरठ पुलिस सतर्क है। खुफिया अलर्ट पर टोल और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच जारी है।

दिल्ली की जेलों में भ्रष्टाचार उजागर, सहायक अधीक्षक सहित पांच गिरफ्तार

रोहिणी जेल में रिश्वत और वसूली के संगठित नेटवर्क का खुलासा, सहायक अधीक्षक समेत पांच आरोपियों पर एसीबी का शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एक बार फिर उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने रोहिणी जेल में कैदियों से सुरक्षा और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में सहायक अधीक्षक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपित संगठित तरीके से कैदियों और उनके स्वजन से धन उगाही कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जेल के भीतर कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों की मिलीभगत से लंबे समय से यह नेटवर्क सक्रिय था। आरोप है कि कैदियों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, मुलाकात में सहूलियत और अन्य लाभ दिलाने के बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस मामले में यह पहली कार्रवाई नहीं है। इसी वर्ष फरवरी में भी इसी गिरोह से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही गिरफ्तारियां इस बात का संकेत हैं कि जेलों में भ्रष्टाचार की समस्या गहरी जड़ें जमा चुकी है। जांच एजेंसियां अब पुराने मामलों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर रही हैं ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली की जेलों में पहले भी कैदियों से वसूली, पैसे लेकर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिबंधित वस्तुएं और मादक पदार्थ पहुंचाने, हिंसक झड़प तथा हत्या जैसी कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन मामलों ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में पारदर्शिता बढ़ाने, निगरानी तंत्र मजबूत करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से ही ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।

रोहिणी जेल वसूली कांड में पांच आरोपी गिरफ्तार

फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जेलों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित निगरानी, पारदर्शी व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कैदियों को नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाएं निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध कराई जाएं और जेल कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, तो इस तरह की अवैध वसूली की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। एसीबी अब इस मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन, संदिग्ध संपर्कों और अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जेल व्यवस्था में पारदर्शिता तथा लोगों का विश्वास मजबूत किया जा सके। एसीबी अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है और जेल से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन तथा कर्मचारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि वसूली का यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इससे कितने कैदी प्रभावित हुए। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान अन्य कर्मचारियों या बाहरी लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

बीबीए में प्रवेश का मौका, समय रहते पूरा करें ऑनलाइन आवेदन

एजेंसी, नई दिल्ली

31 जुलाई को सेक्टर-40 स्थित परिसर में बीबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित संस्थान ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद अभ्यर्थियों को उसकी प्रति सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि काउंसलिंग के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाणपत्रों और उनकी प्रतियों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। संस्थान के अनुसार सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की योग्यता, उपलब्ध सीटों तथा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा।

रेवाड़ी जेल में कैदियों के पुनर्वास की नई पहल,एक माह का होटल मैनेजमेंट कोर्स शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली

रेवाड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकड्डरण (डीएलएसए), इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर और जिला जेल रेवाड़ी ने कैदियों के पुनर्वास एवं कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के दिशा-निर्देशों के तहत इन संस्थानों के बीच एक एमओयू किया गया है।

डीएलएसए सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि इस समझौते के तहत जिला जेल में बंद कैदियों के लिए होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का एक माह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। कोर्स के दौरान कैदियों को कुकिंग, सर्विंग, रेस्टोरेंट संचालन, व्यक्तित्व विकास और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्हें कम लागत में ढाबा, रेस्टोरेंट या कैटरिंग व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि रिहाई के बाद वे रोजगार प्राप्त कर सकें।

इस अवसर पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. असीम मिगलानी, सीजेएम डॉ. रेनू सोलखे, जिला जेल अधीक्षक रेशम सिंह, होटल मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष डॉ. अदिति शर्मा सहित अन्य अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगी।

न्यूज ब्रीफ

पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन की हर पहलू से जांच जारी

भारतेंदु संवाददाता, अनंतनाग। अनंतनाग में पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। करीब 33 महीने बाद घाटी में किसी पुलिसकर्मी को निशाना बनाकर की गई इस टारगेट किलिंग ने आतंकियों की बदलती रणनीति को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। शुरुआती जांच में स्थानीय आतंकी नेटवर्क के साथ एक पाकिस्तानी आतंकवादी की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रतिबंधित संगठन टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, जिसकी भी जांच की जा रही है।

भूस्खलन और भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर एनएच-44 और डोडा-किश्तवाड़ रोड बंद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। गुरुवार को भारी बारिश के कारण कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन, पत्थर और मालवा गिरने की घटनाओं के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (एनएच -44) पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है जिससे इस अहम रास्ते पर यातायात बाधित हुआ है। अधिकारियों के अनुसार लगातार बारिश और भूस्खलन व मलबे के जमा होने से सड़क की हालत असुरक्षित हो गई है जिसके चलते डोडा-किश्तवाड़ रोड भी बंद कर दी गई है।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 2.5 करोड़ रुपए के शॉल धोखाधड़ी मामले में चार लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने 2.5 करोड़ रुपये की कथित शॉल धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुनाफ़े का वादा करके एक व्यापारी से शॉल लिए और फिर उनका भुगतान नहीं किया। ईओडब्ल्यू द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने एफआईआर नंबर 55/2022 के तहत (धारा 420, 120-बी और 201 आरपीसी) श्रीनगर की 'सब-जज स्मॉल कॉज़ेस कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर इस मामले में शामिल होने का आरोप है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जम्मू शहर में नगर निगम ने तैयारियों को किया तेज

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा समय में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। इसी के दौरान मौसम विभाग ने भी बारिशों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इन बारिशों के कारण जम्मू-कश्मीर में काफी ज्यादा नुकसान और तबाही देखने को मिल रही है। वहीं जम्मू शहर में भारी बारिश के बाद सुबह-सुबह ही जम्मू नगर निगम ने मॉनसून की तैयारियों को और तेज कर दिया है।

शोपियां में घर में घुसा तेंदुआ, 6 साल की बच्ची घायल

भारतेंदु संवाददाता, शोपियां। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले के केलर इलाके में लैत्री वाली बेहक के जंगल वाले इलाके में एक घर में तेंदुआ घुस गया जिससे छह साल की एक बच्ची घायल हो गई।एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ केलर में एक घर में घुस गया और उसने बच्ची पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गई। उन्होंने बताया कि घायल बच्ची को तुरंत इलाज के लिए ज़िला अस्पताल शोपियां ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

भाजपा ने उठाए एमबीबीएस घोटाले के मुद्दे

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने गुरुवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग यह नहीं भूले हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सबसे बड़े एमबीबीएस प्रवेश घोटाले के मुख्य आरोपी को न केवल कार्यकाल विस्तार देकर बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सलाहकार के पद पर नियुक्त करके भी पुरस्कृत किया था। एक बयान में शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को पारदर्शिता और जवाबदेही पर उपदेश देने का अधिकार नहीं है क्योंकि एमबीबीएस पेपर बेचने के घोटाले के मुख्य आरोपी के प्रमुख संरक्षक होने का कलंक उन्हीं पर है।

बादल फटने से उड़ी में बह गए कई घर, परिवार हुए बेघर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के उड़ी बिजहामा के मायन इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। अचानक आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण कई घर बह गए और सड़कों पर मलबा जमा हो गया। घटना के बाद कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

घर गिराना समाधान नहीं, लोगों का भरोसा जीतना होगा : उमर अब्दुल्ला

बोले- आतंकवाद से सख्ती से निपटें लेकिन निर्दोषों के अधिकारों की भी करें रक्षा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस के गुस्से और पीड़ा को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि ड्यूटी के दौरान अपने साथियों को खोना किसी भी पुलिस बल के लिए बेहद दुखद और भावनात्मक स्थिति होती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में भी कानून और संविधान की मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाइयों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी को उन्हीं के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री का यह बयान हाल ही में एक हेड कांस्टेबल की हत्या के बाद सामने आया है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और कथित तौर पर कुछ घरों को ध्वस्त किए जाने जैसे मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई थी।

कानून व्यवस्था पर उमर का संदेश, न्याय हो लेकिन संविधान के अनुसार।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन ऐसी कार्रवाई का दायरा केवल दोषियों तक सीमित रहना चाहिए। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के कार्रवाई का सामना करना पड़ता है तो इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत कानून का शासन होता है। यदि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो संविधान और न्यायिक दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, तो इससे समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हर कार्रवाई तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकती।

उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस घटना के बाद भी कई निर्दोष लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्दोष नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

कानून के दायरे में हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में केवल सख्ती से शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए जनता का विश्वास जीतना भी उतना ही आवश्यक है। जब लोग यह महसूस करेंगे कि सरकार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है, तभी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों से अपील की कि वे कानून के दायरे में रहकर कार्य करें।

जेएंडके में लगातार बारिश से 126 सड़कें बंद और 500 से अधिक गांवों का टूटा संपर्क

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और सड़कें बंद होने से सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से गिरे बड़े पत्थर की चपेट में आने से एक दंपती की मौत हो गई। वहीं बांदीपोरा जिले में अचानक आई बाढ़ में एक महिला और उसके 14 वर्षीय बेटे की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं।

लगातार बारिश के कारण प्रदेशभर में 126 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे 500 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। कई नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर हैं तथा निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारामुला, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ और सांबा समेत कई जिलों में भूस्खलन और सड़क क्षति की घटनाएं सामने आई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने, राहत कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सेवाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है।

कई जिलों में तबाही के बीच राहत और बचाव अभियान तेज

माता वैष्णो देवी यात्रा पांचवें दिन भी रुकी, कटड़ा में फंसे 15 हजार श्रद्धालु

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा गुरुवार को लगातार पांचवें दिन भी स्थगित रही। यात्रा बंद रहने से देश के विभिन्न राज्यों से कटड़ा पहुंचे करीब 15 हजार श्रद्धालु यात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

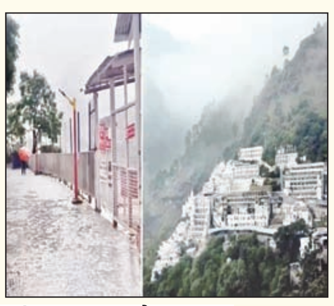

लगातार वर्षा के चलते बैटरी कार मार्ग और भवन क्षेत्र सहित कई स्थानों पर पहाड़ियों से मलबा, चट्टानें और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यात्रा मार्ग को असुरक्षित घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा बहाल नहीं करने का निर्णय लिया है। श्राइन बोर्ड के सफाई कर्मचारी, आपदा प्रबंधन दल, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभाग लगातार मलबा हटाने तथा मार्ग को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि मौसम में सुधार और सभी रास्तों के पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।

हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवाएं भी ठप

अनंतनाग हमले के बाद घाटी में हाई अलर्ट

अनंतनाग हमले के बाद आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में जुटे सुरक्षाबल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। पुलिस, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे कश्मीर घाटी में व्यापक तलाशी और सत्यापन अभियान शुरू किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादी संगठनों को स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को कमजोर किए बिना आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, शोपियां, गांदरबल सहित कई जिलों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। अभियान के दौरान 2500 से अधिक संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स को पूछताछ और सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से आतंकियों के संपर्क, वित्तीय लेनदेन, संचार माध्यमों और संभावित सहयोग के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हालिया हमले के बाद प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियों का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों और नेटवर्क की पहचान करना है जो आतंकियों को आश्रय, परिवहन, धन, संचार उपकरण या अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की है ताकि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी सुराग को जुटाया जा सके। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और प्रमुख बाजारों, सरकारी प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी की जा रही है।

पहाड़ी रास्तों पर बारिश का खतरा, डोडा में बड़ा सड़क हादसा।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर की जा रही है और निर्दोष नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी आतंकी नेटवर्क को सक्रिय होने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ केवल मुठभेड़ों से ही नहीं बल्कि उसके पूरे समर्थन तंत्र को समाप्त करने से स्थायी सफलता मिल सकती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के मददगारों, वित्तीय नेटवर्क और संचार तंत्र पर लगातार निगरानी रख रही हैं। अनंतनाग की घटना के बाद शुरू किया गया यह अभियान घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

2500 से अधिक संदिग्ध हिरासत में

संग्रामा के पूर्व विधायक शोएब नबी लोन फिर पीडीपी में शामिल

फिर पीडीपी में शामिल हुए पूर्व विधायक शोएब नबी लोन, महबूबा मुफ्ती ने बताया 'घर वापसी'

भारतेंदु संवाददाता, बांदीपोरा

जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत संग्रामा के पूर्व विधायक शोएब नबी लोन ने एक बार फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का दामन थाम लिया है। उनकी वापसी का पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए इसे 'घर वापसी' बताया। उन्होंने कहा कि शोएब नबी लोन का पीडीपी से पुराना और गहरा संबंध रहा है तथा उनकी वापसी से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। शोएब के पिता स्वर्गीय डॉ. गुलाम नबी लोन पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और उन्होंने पार्टी को मजबूत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में शोएब की वापसी को केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि पारिवारिक और वैचारिक रिश्तों की पुनर्स्थापना के रूप में भी देखा जा रहा है।

पीडीपी में दोबारा शामिल होने के बाद शोएब नबी लोन ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इसी दल से हुई थी और पार्टी की विचारधारा तथा मूल एजेंडा आज भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि वह जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पीडीपी लगातार संघर्ष करती रही है और वह इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए लौटे हैं।

पार्टी के मूल एजेंडे को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

जेकेएसएसबी पेपर लीक को लेकर उमर अब्दुल्ला और नड्डा आमने-सामने

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों और तारीखों को सही ढंग से देखा जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस पेपर लीक का उल्लेख किया जा रहा है, वह वर्ष 2022 में हुआ था। उस समय जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन था। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में आरोप लगाने से पहले वास्तविक परिस्थितियों और समय का ध्यान रखना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है। उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों पर राजनीति करने के बजाय पारदर्शी जांच और दोषियों को सजा दिलाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नीट दोषियों को जल्द मिलेगी सजा :भाजपा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता और ताहिर चौधरी ने कहा कि देश में पहली बार पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि छात्रों को जल्द न्याय मिल सके और दोषियों को शीघ्र सजा दी जा सके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

लगातार बारिश से उफान पर तवी निचले इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को नदी ने अलर्ट स्तर को पार कर लिया और खतरे के निशान से महज करीब आधा मीटर नीचे पहुंच गई। इस स्थिति ने जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में नदी, नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों के पास न जाएं तथा मौसम और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार सलमेय पुल स्थित गेज स्टेशन पर गुरुवार दोपहर लगभग एक बजे तवी नदी का जलस्तर 18.315 फीट दर्ज किया गया। यह निर्धारित 15 फीट के अलर्ट स्तर से काफी ऊपर है, जबकि 20 फीट के खतरे के निशान से केवल 1.685 फीट यानी लगभग आधा मीटर कम है।

उधमपुर में तवी नदी खतरे के निशान से आधा मीटर दूर

जम्मू कश्मीर में बारिश का नया दौर शुरू कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

भारतेंदु संवाददाता, बडगाम। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह आठ बजे जारी ताजा मौसम बुलेटिन में बताया कि जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। विभाग के अनुसार यह वर्षा प्रणाली उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है और अगले कुछ घंटों में मुख्य रूप से सांबा, कठुआ, उधमपुर तथा चिनाब घाटी के जिलों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद मौसम प्रणाली के दक्षिण कश्मीर तक पहुंचने की संभावना है, जहां अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि मौजूदा दौर के समाप्त होने के बाद शुक्रवार को भी जम्मू-कश्मीर में एक और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिमी विक्षोभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रभाव से कश्मीर क्षेत्र में नमी बढ़ी है और घने बादलों का निर्माण हो रहा है, जिससे लगातार वर्षा की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

जम्मू संभाग के कई जिलों में तेज बारिश के आसार

आगाज श्रीनगर में असेंड जेएंडके 2026 का आगाज, मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिया आत्मविश्वास का संदेश

उद्यमिता और नवाचार से बदलेगा जेएंडके का भविष्य

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित असेंड जे एंड के 2026 स्टार्टअप इकोसिस्टम समिट के उद्घाटन अवसर पर युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी चीज से डरना है तो वह कोशिश न करने का डर होना चाहिए। उनका कहना था कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं और वही अनुभव भविष्य की उपलब्धियों की मजबूत नींव बनते हैं। उन्होंने युवाओं से नई सोच अपनाने, जोखिम लेने और नवाचार के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया।

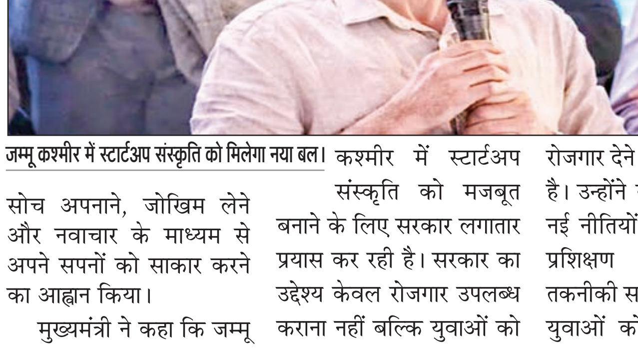
जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप संस्कृति को मिलेगा नया बल।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। उन्होंने बताया कि प्रशासन नई नीतियों, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी सहयोग के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर देश के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में अपनी पहचान बनाएगा।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में पर्यटन, कृषि, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि युवा आधुनिक तकनीक और नए विचारों के साथ इन क्षेत्रों में काम करें तो वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि हजारों अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

आतंकियों के खिलाफ खुफिया अभियान होगा और तेज: एलजी सिन्हा

बोले- अमरनाथ यात्रा में नहीं होगी सुरक्षा चूक, हर खतरे पर नजर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने आतंकवाद के खिलाफ खुफिया अभियानों को और तेज करने को कहा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि किसी भी संभावित खतरे की पहचान समय रहते कर उसे निष्प्रभावी बनाया जाए।

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यात्रा के दौरान बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया।

न्यूज ब्रीफ

सीएम ने आपदा प्रभावितों से फोन पर बातचीत की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गत दिवस शिमला से कांगड़ा जिला की बोह घाटी में बादल फटने की घटना के संबंध में कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा तथा प्रभावित परिवारों से दूरभाष पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। डीसी इस दौरान घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा जिला प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र और हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि वे शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्वयं नुकसान का आकलन करेंगे। जिन परिवारों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

सीएम ने नंद लाल शर्मा के निधन पर शोक जताया

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के पूर्व अध्यक्ष नंद लाल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नंद लाल शर्मा का हरियाणा के पंचकूला में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद लाल शर्मा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रदेश की जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल को सुदृढ़ बनाने में भी नंद लाल शर्मा का योगदान सराहनीय रहा। सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और शोकाकुल परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

25 जुलाई को कांग्रेस सुजानपुर में करेगी प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस 25 जुलाई को सुबह 11 बजे सुजानपुर में विरोध-प्रदर्शन करेगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा ने बताया कि सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व समर्थक मुरली मनोहर मंदिर में एकत्रित होंगे। इसके बाद मिनी सचिवालय तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, जिला व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधि, युवा कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। राजेंद्र वर्मा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों, नेताओं और छात्रों के साथ हुई कथित घटना के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी। साथ ही परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और उनसे जुड़े व्यवस्थागत मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने तथा विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर एवं आपराधिक मामले वापस लेने की मांग भी उठाई जाएगी।

विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस के एंटी-चिट्टा ड्रग्स अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय झुखाला, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान झुखाला तथा राजकीय महाविद्यालय नयनादेवी में नशा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस उपअधीक्षक मदन धीमान ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को चिट्टा/हेरोइन सहित अन्य नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं, एसडीपीओ नयनादेवी विक्रांत बौंसरा ने नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों और नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ खुली चर्चा हुई, जिसमें नशा उन्मूलन व युवाओं की भूमिका पर विचार साझा किए गए। विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

कारगिल विजय दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। कारगिल विजय दिवस रविवार को हमीरपुर में पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने समारोह की तैयारियां पूरी करने के लिए कवायद तेज कर दी है। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने वीरवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क एवं निर्माणाधीन युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित विभागों और नगर निगम अधिकारियों को आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण विभाग को अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके परिजनों को आमंत्रित करने को कहा गया। बैठक में एसपी बलवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दो वाहनों से 910 ग्राम चरस बरामद, पांच काबू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्शन टीम ने घराससनी फोरलेन लिंक रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो वाहनों से 910 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने दो वाहन की जांच के दौरान यह नशीला पदार्थ बरामद किया। इस मामले में थाना झंडूता में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरव कुमार (28) और उसकी पत्नी अक्षा (28), निवासी विकास नगर, पटोली जिला जम्मू-कश्मीर; हरीश ठाकुर (20), निवासी पाखला, तहसील जरी, जिला कुल्लू; सुमंत शर्मा (22), निवासी धरमेर, तहसील जरी, जिला कुल्लू तथा प्रियांशु ठाकुर (21), निवासी बगयाड़ा, तहसील जरी, जिला कुल्लू शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद मादक पदार्थ के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों व नेटवर्क की जांच जारी है।

25 को बैरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिजली उपमंडल-1 के सहायक अधिशाषी अभियंता ई. सन्नी जगोता ने बताया कि 25 जुलाई को बैरी अनुभाग में बिजली की लाइनों की आवश्यक मरम्मत व पेड़ों की कांट-छांट के कार्य के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि बरमाना, कैंचीमोड़, गुग्गाघटेड़, खलेड़, लघट, नालाचांगर, बैरी रजादियां, बीडीटीएस ग्राउंड सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि शटडाउन मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

गाहर-केट सड़क मार्ग 10 अगस्त तक बंद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए गाहर से केट सड़क मार्ग को आगामी 10 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग घुमारवीं उपमंडल द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत के चलते यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन दधोल से जरोह सड़क मार्ग से आवाजाही करें। मरम्मत कार्य के दौरान केवल एंबुलेंस, स्कूल बस, वीआईपी और आपातकालीन सेवा वाहनों को अनुमति रहेगी।

असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन 30 से

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सहायक स्टाफ नर्स के पदों के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों से 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से 29 अगस्त 2026 रात 11.59 मिनट तक खुला रहेगा। यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

भाजपा की बैठक में संगठन मजबूती पर हुआ मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, सुंदरनगर। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व सुंदरनगर विधायक राकेश जमवाल ने बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी, पूर्व अधिकारी और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। राकेश जमवाल ने कहा कि पूर्व कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर संगठन और समाज के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ को प्रभावी मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। जमवाल ने सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा उनकी मांगों को हर मंच पर उठाएगी। कार्यक्रम में चेतराम, चमन शर्मा और तिहेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

कई जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट, बारिश से 178 सड़कें बंद, 141 ट्रांसफार्मर ठप

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में वीरवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। कुछ इलाकों में व्यापक बारिश हुई। लगातार बारिश से कई नदियां, खड्डें और बरसाती नाले उफान पर हैं।

मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के लिए येलो और ओरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के पास नहीं जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 25 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 जुलाई को मानसून के और सक्रिय होने की संभावना है। इस दिन कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि सोलन, चंबा और बिलासपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 27, 28 और 29 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में बिलासपुर जिले के नैना देवी में 56.2 मिलीमीटर, मलरांव में 49.4 मिलीमीटर, कुल्लू के मनाली में 35.0 मिलीमीटर, शिमला के रामपुर में 30.3 मिलीमीटर, बिलासपुर के ब्रह्माणी में 29.4 मिलीमीटर, शिमला के सराहन में 28.7 मिलीमीटर, सिरमौर के नाहन में 27.8 मिलीमीटर, कुल्लू के कोठी में 26.0 मिलीमीटर, शिमला के रोहड़ू में 20.0 मिलीमीटर और खदराला में 19.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि पिछले 24 घंटों में बारिश की तीव्रता पहले के मुकाबले कुछ कम रही, लेकिन लगातार बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार वीरवार तक प्रदेश में भूस्खलन के कारण 178 सड़कें बंद हैं। सबसे अधिक 71 सड़कें मंडी जिले में अवरुद्ध रहीं। कुल्लू में 36, सिरमौर में 29, चंबा में 16, शिमला में 14, कांगड़ा में छह और लाहौल-स्पीति में पांच सड़कें बंद रहीं। बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। प्रदेश में 141 ट्रांसफार्मर खराब होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इनमें सोलन में सबसे अधिक 70 ट्रांसफार्मर बंद रहे। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में 30, मंडी में 29 और शिमला में 10 ट्रांसफार्मर प्रभावित रहे। पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। प्रदेश में 188 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिनमें अकेले चंबा जिले की 148 योजनाएं बंद हैं। संबंधित विभाग सड़कें खोलने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और पेयजल योजनाओं को फिर से चालू करने में जुटे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 24 से 26 जुलाई के दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। उन्होंने लोगों से नदी-नालों और खड्डों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

विपक्ष युवाओं के कंधों पर राजनीति करना बंद करे, चर्चा में भाग ले : अनुराग ठाकुर

◆ युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही सरकार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत के युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य और आकांक्षाओं को भली-भांति समझती है।

इसी सोच के साथ पिछले 12 वर्षों में युवाओं के कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों युवाओं को मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वह युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति करने से बाज आएं। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद सबसे प्रभावी माध्यम हैं, इसलिए विपक्ष को संसद में चर्चा से भागने के बजाय उसमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। देश का युवा समाधान चाहता है, भ्रम और राजनीतिक स्वार्थ नहीं। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का लिया गया निर्णय अत्यंत स्वागतयोग्य और अभिनंदनीय है। इससे छात्रों से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण होगा तथा युवाओं का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, पारदर्शिता, सुशासन व अवसरों के विस्तार के संकल्प को सशक्त करने वाला है। देश का युवा आज विकास, अवसर और न्याय की राजनीति के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भगेटू गांव के तीन युवाओं ने जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप में जीते गोल्ड, सिल्वर व ब्रांज मेडल

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप में विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर की ग्राम पंचायत भगेटू के गांव भगेटू के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र, विद्यालय और पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया।

32 किलोग्राम भार वर्ग में आदित्य ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, अक्षय कुमार ने रजत पदक सिल्वर मेडल तथा रुद्र ठाकुर ने ब्रांज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। तीनों खिलाड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैड़ के छात्र हैं। अपनी इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों ने अपने प्रशिक्षक अनूप शर्मा को देते हुए कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन, अनुशासित प्रशिक्षण व निरंतर प्रोत्साहन से ही वे यह उपलब्धि हासिल कर सके। तीनों खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय सफलता पर क्षेत्रवासियों, अभिभावकों व विद्यालय परिवार ने उन्हें तथा उनके प्रशिक्षक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से गांव भगेटू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैड़ और जिला हमीरपुर का गौरव बढ़ा है। सभी ने आशा व्यक्त की कि ये खिलाड़ी भविष्य में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

कानून व सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जारी रहेगी किन्नौर कैलाश यात्रा

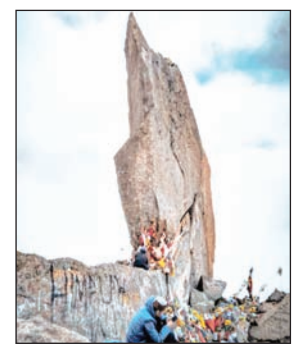

◆ रोक लगाने के पौवारी पंचायत के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पौवारी ग्राम पंचायत द्वारा किन्नौर कैलाश यात्रा को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखें। न्यायालय ने पौवारी ग्राम पंचायत को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह मामला प्रकाशंकरस किन्नर कैलाश यात्रा और एक अन्य पंजीकृत संस्था द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। ये संस्थाएं हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत हैं व किन्नौर जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार वार्षिक किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन करती हैं। याचिकाकर्ताओं ने पौवारी ग्राम पंचायत के 13 जुलाई को पारित उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी, जिसमें यात्रा को स्थायी रूप से रोकने और याचिकाकर्ता संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पौवारी ग्राम पंचायत ने एक ग्राम सभा बैठक के बाद यह प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बहुमत (112 के मुकाबले 62 हस्ताक्षर) से यात्रा रोकने का निर्णय लिया गया था। ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ता संस्था को भी भंग करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ग्राम पंचायत को पंजीकृत संस्थाओं को भंग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों, जिसमें राजस्व सचिव, पंचायती राज सचिव, उपायुक्त किन्नौर, एसडीएम कल्पा व अध्यक्ष किन्नौर कैलाश यात्रा आयोजन समिति, पुलिस अधीक्षक किन्नौर और ब्लॉक विकास अधिकारी कल्पा शामिल हैं, उनको यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि यात्रा सभी कानूनों व सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए जारी रहे। जिला प्रशासन, विशेष रूप से उपायुक्त किन्नौर, एसडीएम कल्पा और पुलिस अधीक्षक किन्नौर की जिम्मेदारी होगी कि वे यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है।

कंदरोड़ी रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के तहत थाना डमटाल क्षेत्र में कंदरोड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। उसे उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर डमटाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक डॉक्टर की पर्ची मिली, जिसमें उसका नाम लालू यादव, उम्र 62 वर्ष दर्ज है। इसके अलावा कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने शव को पहचान के लिए 72 घंटे तक नूरपुर अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखा है और लोगों से मृतक की पहचान कराने में सहयोग की अपील की है।

अग्निवीर भर्ती रैली अणु के ग्राउंड में 26 सितंबर से

4571 युवाओं का होगा ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। थल सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने वाले युवाओं के ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कालेज परिसर में 26 सितंबर से 6 अक्तूबर तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।

थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने जिला प्रशासन के सहयोग से इस भर्ती रैली की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। डीसी गंधर्वा राठौड़ ने वीरवार को यहां हमीर भवन में थल सेना भर्ती कार्यालय व जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके इस रैली की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी ने कहा कि इसी वर्ष मार्च में भी यहीं पर भर्ती रैली आयोजित की जा चुकी है। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारी पिछली रैली के अनुभव के आधार सभी आवश्यक प्रबंध करें। उन्होंने बताया कि इस बार जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के अलावा क्लर्क श्रेणी की भर्ती में प्रदेश के अन्य जिलों के युवाओं को भी बुलाया गया है, जिससे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4571 होगी। यानि प्रत्येक दिन लगभग 550 युवाओं का ग्राउंड टेस्ट होगा। यह प्रक्रिया 4 अक्तूबर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

मौसम खराब रहने की स्थिति के लिए 5 और 6 अक्तूबर को रिजर्व दिन रखे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए आने वाले सेना के लगभग 200 अधिकारियों एवं सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी करनी होगी। उपायुक्त ने रैली स्थल पर बिजली, पानी, अग्निशमन, शौचालय एवं सफाई, मेडिकल, इंटरनेट, कंप्यूटर-प्रिंटर्स और अन्य सुविधाओं तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा विभाग, युवा सेवाएं व खेल विभाग, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों से भी अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

पात्र उम्मीदवारों की मैदान में एंट्री तड़के से ही शुरू हो जाएगी। इस दौरान बस सेवाएं उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता एवं प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों के प्रयोग और रैली स्थल के आस-पास संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। उपायुक्त ने सीएमओ से कहा कि वे इस संबंध में सभी दवा विक्रेताओं को भी विशेष दिशा-निर्देश जारी करें। बैठक में सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने भर्ती रैली और इससे संबंधित विभिन्न प्रबंधों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बिलासपुर कॉलेज के परिसर में लगाए 80 पौधे

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से ब्यूटीफिकेशन कमेटी ने दूसरे चरण के तहत करीब 80 पौधे लगाए हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में भी कमेटी ने लगभग 50 पौधे रोपे थे।

इस बार मोरपंखी, अशोक व पाम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में करीब 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरण अनुकूल परिसर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से विभिन्न समितियां छात्र हित में लगातार कार्य कर रही हैं। प्राचार्य ने ब्यूटीफिकेशन कमेटी की संयोजक डॉ. रितु शर्मा तथा सदस्यों डॉ. मोनिका, डॉ. नम्रता, डॉ. मनोहर, प्रो. अनुप्रिया, प्रो. हितेश, प्रो. सोनिका, प्रो. रोहिणी और प्रो. अमित के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

नीति महाजन बनीं नूरपुर नप अध्यक्ष सोनिया ने ली उपाध्यक्ष पद की शपथ

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। नगर परिषद नूरपुर के सभागार में वीरवार को आयोजित गरिमामय समारोह में नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीति महाजन तथा उपाध्यक्ष सोनिया सोगा ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने दोनों जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई व उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष नीति महाजन व उपाध्यक्ष सोनिया सोगा ने नगर के सर्वांगीण विकास, पारदर्शी प्रशासन व जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के सभी पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से विकास कार्यों को गति दी जाएगी तथा नागरिकों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार व जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। समारोह में पूर्व विधायक अजय महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि नया नेतृत्व नगर के विकास व जनसेवा के कार्यों को नई दिशा देगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय, पारदर्शिता व जनहित की भावना से कार्य करने का आह्वान किया, ताकि नूरपुर के समग्र विकास को नई गति मिल सके। इस अवसर पर वन विकास निगम के निदेशक योगेश महाजन, डीएसपी चंद्रपाल सिंह, नगर परिषद के सभी पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह का समापन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने और नगर के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हुआ।

राकेश ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए सक्रियता और अनुशासन के साथ काम करने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मट्टन सिद्ध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। इसमें जिले के सभी 10 मंडलों के मंडल अध्यक्षों एवं महामंत्रियों सहित विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य देसराज शर्मा, प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक अनिल धीमान, जिला महामंत्री अजय रिंटू व राजेश सहगल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संधारित करने के संबंध में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना था। इस दौरान बैठकों, निर्णयों और गतिविधियों के सही दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में जिले के सभी मंडलों की अब तक की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। डिजिटल प्रशिक्षण अभियान, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा कर आगामी योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसके अलावा संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी 532 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण करवाया जाएगा। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे संगठन द्वारा निर्धारित अभियानों और कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा, अनुशासन और सक्रियता के साथ सफल बनाएं तथा सभी गतिविधियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करें।

निगरानी शाहपुरकंडी बैराज बांध की झील खतरे के निशान से केवल 2.40 मीटर नीचे

पठानकोट के माधोपुर से पाकिस्तान को छोड़ा पानी

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। बीते 2 दिन से शाहपुरकंडी, पठानकोट और हिमाचल में हो रही भारी वर्षा होने व चमेरा प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में पानी रणजीत सागर बांध में पहुंच रहा है, जिससे एक तरफ जहां आरएसडी झील का जलस्तर एक मीटर बढ़ गया है। वहीं, अब शाहपुरकंडी बैराज बांध में पानी झील के खतरे के निशान तक पहुंच करने लगा है।

शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील खतरे के निशान से केवल 2.40 मीटर ही कम है। इसके चलते माधोपुर हेडवर्क्स से पाकिस्तान व नहरों में पानी का डिस्चार्ज माधोपुर हेडवर्क्स में अधिक मात्रा में पानी आने से पाकिस्तान की तरफ 52 गेटों में से 4 गेटों को 4 फुट तक ऊंचा उठाकर 23 हजार क्यूसेक पानी बहाव पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। बता दें, रणजीत सागर बांध परियोजना की झील का जलस्तर एक दिन में एक मीटर बढ़ने के बाद 503.22 मीटर तक आ गया है, जबकि गत दिवस यह जलस्तर 502.23 मीटर था। चमेरा प्रोजेक्ट व सेवा हाइडल प्रोजेक्ट से 92,071 क्यूसेक का भारी बहाव आने से रणजीत सागर बांध परियोजना की झील के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, बांध परियोजना की झील में अधिकतम 527.91 मीटर तक जल रखने की क्षमता है। दूसरी तरफ शाहपुर कंडी बैराज बांध भी लबालब हो रहा है, जिससे बैराज बांध की झील का जलस्तर 402.10 मीटर तक पहुंच गया है। निचले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की मांग कम होने के कारण बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कम कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि चार यूनिटों में से 2 यूनिटों को चलाकर 62 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है और आरएसडी बांध परियोजना से 21,010 क्यूसेक पानी का बहाव शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील में छोड़ा जा रहा है। शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील खतरे के निशान से केवल 2.40 मीटर ही कम है। शाहपुर कंडी बैराज बांध से माधोपुर हेडवर्क्स की ओर 13,010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही माधोपुर हेडवर्क्स से विभिन्न नहरों में पानी का डिस्चार्ज इस प्रकार है। यूबीडीसी नहर: 3,243 क्यूसेकएमबी लिंक नहर: 6,000 क्यूसेककश्मीर कैनाल: 200 क्यूसेकइस्लामपुर नहर: 50 क्यूसेक क्षेत्र में दर्ज वर्षा के आंकड़े बांध प्रशासन के अनुसार मानसून की पहली भारी बारिश होने से आरएसडी झील में जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है। विभिन्न स्थानों पर दर्ज की गई वर्षा का ब्योरा:स्थानदर्ज वर्षा (मिमी)पूंड़ 141.05 मिमीशाहपुर कंडी 115 मिमीपट्टी 101.08 मिमीआरएसडी 67.2 मिमीखेरी 65 मिमीसारटी फंगोटा 64 मिमी।

जिनी बुशार का खूबसूरत अंदाज

कनाडा। जिनी बुशार कनाडा की प्रसिद्ध पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 25 फरवरी 1994 को वेस्टमाउंट, क्यूबेक, कनाडा में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था।

पीवी सिंधू चाइना ओपन से बाहर

चीन की चेन युफेई से 21-16, 20-22, 18-21 से हराया

एजेंसी, चांग्झू

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और वीरवार को यहां दूसरे दौर के मैच में चीन की खिलाड़ी चेन युफेई से तीन गेम के कड़े मुकाबले में हारकर चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। लगभग डेढ़ घंटे तक चले इस मैराथन मुकाबले में सिंधू विश्व में चौथे नंबर की खिलाड़ी युफेई से 21-16, 20-22, 18-21 से हार गईं।

हैदराबाद की रहने वाली 30 वर्षीय सिंधू ने पिछले सप्ताह जापान ओपन जीतकर लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म किया था और उन्हें इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। पहले गेम से ही यह स्पष्ट हो गया था कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में 7-13 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 16-16 कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लगातार पांच अंक हासिल करके पहला गेम अपने नाम कर दिया। दूसरे गेम में वापसी करने की बारी चेन की थी। सिंधू ने चार मैच प्वाइंट गंवाए। तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली चेन ने 16-20 की स्थिति से वापसी करते हुए यह गेम 22-20 से जीत लिया।

तीसरे और निर्णायक गेम में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन अंत में चेन ने 17-17 के स्कोर से बढ़त बनाकर मैच अपने नाम कर दिया।

कुलदीप यादव ने यॉर्कशर से किया अनुबंध, खेलेंगे 8 मैच

एजेंसी, लीड्स

भारत की एकादश में बार-बार अनदेखी किए जाने के बाद बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने शीर्ष इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशर के लिए मौजूदा सत्र में आठ मैच खेलने का करार किया। यॉर्कशर काउंटी क्रिकेट क्लब ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा की, ''यॉर्कशर काउंटी क्रिकेट क्लब को भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्पिनर कुलदीप यादव के साथ विदेशी खिलाड़ी के तौर पर करार करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 31 साल के कुलदीप 'मेट्रो बैंक एकदिवसीय कप' के पांच मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे और फिर सितंबर में 'रोथसे काउंटी चैंपियनशिप' के आखिरी चार में से तीन मैच खेलने के लिए हैडिंग्ले लौटेंगे।''

कुलदीप शुक्रवार को नीथ में ग्लेमोर्गन के खिलाफ होने वाले 50 ओवर के मैच के लिए टीम में शामिल हो रहे हैं। यॉर्कशर से जुड़ने पर कुलदीप ने कहा, ''मैं यॉर्कशर से जुड़कर बहुत खुश हूं और इस मौके के लिए आभारी हूं। यॉर्कशर जैसे शानदार इतिहास वाले क्लब का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।'' उन्होंने कहा, ''मुझे हमेशा से इंग्लैंड के हालात में खेलने की चुनौती पसंद रही है और प्रबंधन से बात करने के बाद में टीम से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं हैडिंग्ले में टीम के लिए अच्छा योगदान देने को लेकर उत्सुक हूं।'' भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कुलदीप की काबिलियत पर अधिक भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन यॉर्कशर प्रबंधन का मानना है कि इंग्लैंड की गर्म और सूखी गर्मियों में कुलदीप टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

क्लब के क्रिकेट महाप्रबंधक गैविन हैमिल्टन ने कहा, ''कुलदीप अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो इन मुकाबलों के दौरान हमारी टीम को बहुत मजबूती देंगे।'' स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैमिल्टन ने कहा, ''इस बार गर्मी और सूखा मौसम रहा है इसलिए हमें उम्मीद है कि सत्र के आखिरी दौर में स्पिन अहम भूमिका निभाएगी। कुलदीप अपनी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन गेंदबाजी से हमें एक नया आयाम देते हैं और उनके पास शीर्ष स्तर का काफी अनुभव है। हम यॉर्कशर में उनका स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं।'' कुलदीप ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट मैच में 22 की औसत से 79 विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 40 रन देकर पांच विकेट है।

स्पोर्ट्स विंडो

दिल्ली हाफ मैराथन 18 अक्तूबर को, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रोकैम इंटरनेशनल द्वारा आयोजित वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन (वीडीएचएम) अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है। भारत में लंबी दूरी की रेस की संस्कृति को नई पहचान देने वाला यह आयोजन अब केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने, नई पीढ़ी के धावकों को प्रेरित करने, समाज में सहयोग और दान की भावना को मजबूत करने तथा दौड़ की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक व्यापक जनआंदोलन बन चुका है। विश्व एथलेटिक्स की गोल्ड कैटेगरी प्राप्त इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए 23 जुलाई 2026, प्रातः 7 बजे से प्रत्यक्ष और आभासी दोनों श्रेणियों में पंजीकरण शुरू होगा।

भारतीय अंडर-19 टीम ने श्रीलंका को 211 रनों से दी शिकस्त

एजेंसी, कोलंबो। रोहित यादव (चार विकेट) और चिगुरुपति वेंकटा (तीन विकेट) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय अंडर-19 टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन गुरुवार को श्रीलंको 211 रनों से हरा दिया। श्रीलंका अंडर-19 टीम ने कल के चार विकेट पर 155 रनों से आगे खेलना शुरू किया। सुबह के सत्र में 176 रन के स्कोर पर श्रीलंका का पांचवां विकेट कमान विमत दिनसारा (64) रन के रूप में गिरा। उन्हें प्रणव राघवेंद्र ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कविजा गमागे ने पारी को संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान 60वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित यादव ने दुलनित सिगेरा (15) का शिकार कर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर यादव ने जेथन फर्नांडो (शून्य) का भी शिकार कर लिया। 72 ओवर में कविजा गमागे (36) को पाबाथा आउटकर पवेलियन भेज दिया। 77वें ओवर की पांचवी गेंद पर जगनाथन हेमचुदेशन ने सेतमिका सेनेविरत्ने (42) रन को आउट कर श्रीलंका की दूसरी पारी का 260 रन के स्कोर पर अंत कर दिया इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 211 रनों से अपने नाम कर लिया।

वनडे कप डेब्यू पर गेंद से चमके आशुतोष, बल्ले से किया निराश

एजेंसी, नई दिल्ली। हैंपशायर की तरफ से वनडे कप डेब्यू करते हुए रेलवे और दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने तीन विकेट लिए और एक रनआउट में भी योगदान देते हुए अपनी टीम को यॉर्कशायर के खिलाफ 50 रन की बड़ी जीत दिलाई। हालांकि, बल्ले से उन्होंने निराश किया और छठे नंबर पर आते हुए नौ गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। इससे पहले हैंपशायर की तरफ से टॉम प्रेस्ट ने 94 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत पिछले साल की उपविजेता हैंपशायर ने 8 विकेट पर 320 रन बनाए। जेक लेहमन ने भी 75 रन का योगदान दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए इस मैदान पर लिस्ट ए क्रिकेट की रिकॉर्ड साझेदारी की और 140 गेंदों में 147 रन जोड़े। लेहमन को 5 और प्रेस्ट को 73 रन पर जीवनदान मिला।

पाकिस्तान मई 2027 में पांच वनडे मैचों के लिए इंग्लैंड का करेगा दौरा

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मई 2027 में पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा। ये मैच उसी साल बाद में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की तैयारी के तौर पर खेले जाएंगे। सीरीज की शुरुआत 15 मई को साउथम्प्टन में होगी, जिसके बाद मैच मैनचेस्टर (19 मई), लीड्स (21 मई), चेस्टर-ले-स्ट्रीट (23 मई) और कार्डिफ (26 मई) में खेले जाएंगे। 50 ओवर के ये मैच विश्व कप से पहले होंगे, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया 4 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 के बीच करेंगे।

मांडविया ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेल मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित

एजेंसी, ग्लासगो, (स्कॉटलैंड)। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वीरवार को कॉमनवेल्थ खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कॉमनवेल्थ खेल सहयोग के लिए एक मजबूत और सदस्य-संचालित ढांचे का आह्वान किया। आज यहां हुई बैठक में 'एक साथ काम करने की नई सोच: खेल पर कॉमनवेल्थ सहयोग को मजबूत करना' विषय पर डॉ. मांडविया ने कॉमनवेल्थ में खेल प्रशासन, एथलीट कल्याण और संस्थागत क्षमता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश अहमदाबाद में 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।

राष्ट्रमंडल खेलों में लवलीना ने भारत का पहला पदक किया पक्का

एजेंसी, ग्लासगो

लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया जब उन्हें महिलाओं के 75 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिला जिससे कम से कम कांस्य पक्का हो गया। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना को पांच मुक्केबाजों के ड्रॉ में पहले दौर में बाय मिला जिससे अंतिम चार में उनका प्रवेश तय हो गया। लवलीना का सामना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में तुवालु की टीकेबीपी ताफाकी से होगा।

यह 28 वर्ष की लवलीना का राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक है । वह ओलंपिक, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेल और एशियाई चैम्पियनशिप पदक जीत चुकी हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स-2026

भारत का जूडो खिलाड़ी डोप टेस्ट में हुआ फेल

एजेंसी, नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड के दावेदार भारतीय जूडो का अरुण कुमार डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। वह 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल के दावेदार थे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि अरुण से पदक की उम्मीद थी, लेकिन इतने कम समय में उनका विकल्प नहीं चुना जा सकता। मुकेश ने कहा कि हमें बुधवार को नोटिस मिला है, जिसमें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन नियमों के तहत वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इतने कम समय में किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करना भी संभव नहीं है।

फीफा विश्व कप-2026 की ड्रीम इलेवन का ऐलान, मेसी, एम्बाप्पे व हालैंड को मिला स्थान

एजेंसी, ज्यूरिख

फीफा विश्व कप-2026 की प्रशंसकों द्वारा चुनी गई ड्रीम इलेवन की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे, नॉर्वे के एरलिंग हालैंड और इंग्लैंड के जूद बेलिंघम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जगह मिली है। विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा को भी ड्रीम इलेवन में शामिल किया गया है।

40 वर्षीय वोजिन्हा को गोलकीपर के लिए हुए प्रशंसकों के मतदान में 39.6 प्रतिशत वोट मिले। उन्होंने विश्व कप में पदार्पण करने वाले केप वर्डे के लिए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, टूर्नामेंट का गोल्डन ग्लव पुरस्कार स्पेन के उनाई सिमोन को मिला था, जिसका चयन फीफा के तकनीकी समूह ने किया था। विश्व कप से पहले पुर्तगाल के दूसरे डिवीजन क्लब चावेस छोड़ने के बाद वोजिन्हा किसी क्लब से नहीं जुड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्पेन के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ में सात शानदार बचाव किए। इसके अलावा उन्होंने अंतिम-32 मुकाबले में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक खेलने के लिए मजबूर करने में भी अहम भूमिका निभाई।

नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड को फॉरवर्ड खिलाड़ियों के मतदान में 27.5 प्रतिशत वोट मिले। हालैंड ने पांच मैचों में सात गोल दागे और अपनी टीम को पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 2-1 की जीत में दो गोल किए थे। नॉर्वे का सफर इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुआ।

ड्रीम इलेवन में हालैंड और वोजिन्हा के अलावा लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, जूद बेलिंघम, रोद्री, माइकल ओलिसे, पेड्रो पोरो, लिसांद्रो मार्टिनेज, दायो उपामेकानो और मार्क कुकुरेला को भी स्थान मिला है।

आंध्र प्रदेश में एनएच-42 को फोर लेन बनाने के लिए 679.71 करोड़ मंजूर

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में मुदिगुब्बा से कदिरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-42 को दो लेन से चार लेन में विकसित करने के लिए 679.71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई क्षेत्रों की बेंगलुरु-विजयवाड़ा-कोलकाता (बीकेवी) एक्सप्रेसवे, तिरुपति और चेन्नई तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत मौजूदा दो लेन सड़क को पक्के कंधों (पेव्ड शोल्डर) सहित चार लेन राजमार्ग में बदला जाएगा। इस परियोजना से अनंतपुर और श्री सत्य साई जिलों के साथ-साथ कर्नाटक के कुछ हिस्सों से बीकेवी एक्सप्रेसवे, तिरुपति और चेन्नई तक निर्बाध संपर्क स्थापित होगा। इससे यात्रा और माल परिवहन में लगने वाला समय कम होगा, यातायात का दबाव घटेगा तथा क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में चार लेन मुख्य मार्ग, सर्विस रोड, एक फ्लाईओवर, एक वाहन अंडरपास-सह-रोड ओवर ब्रिज (वीयूपी-सह-आरओबी) तथा एक प्रमुख पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम होगी।

प्रियंका गांधी बोलीं-प्रधानमंत्री पेपर लीक की लें जिम्मेदारी

एजेंसी, नई दिल्ली

नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के सांसद खुद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरकार बेहद कमजोर है, जो संसद नहीं चला पा रही।

प्रियंका गांधी ने वीरवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि युवाओं की जायज मांगों के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेते हैं, चाहे मंगल ग्रह पर जाने का हो या ओलंपिक में पदक जीतने का, लेकिन पेपर लीक की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए हैं और इसका श्रेय भी उन्हीं को है।

प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि उन्हें बच्चों की चिंता है, लेकिन रात में उन्हीं बच्चों पर आंसू गैस छोड़ी जाती है और उन्हें पीटा जाता है। अगर मोदी जी हर उपलब्धि का श्रेय लेते हैं तो अब उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। अगर एक भी बच्चे को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी।

नीट पेपर चोरी मामले में अब तक 45 लोगों पर चार्जशीट

संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने स्पष्ट किया है कि नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी और वितरण मामले की जांच में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिला। एजेंसी ने कहा कि मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है।

सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार पुलिस ने नीट (यूजी) परीक्षा का प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला दर्ज किया था। प्रारंभिक संदेह के आधार पर संजीव मुखिया को आरोपित बनाया गया था, क्योंकि उसका नाम अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में सामने आया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

एजेंसी ने बताया कि विस्तृत जांच के दौरान प्रश्नपत्र चोरी, उसके वितरण और उससे लाभान्वित होने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान की गई। इस संबंध में पटना की सक्षम अदालत में 45 आरोपितों के खिलाफ कई आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।

सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया की भूमिका की भी गहन जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वह नीट-यूजी 2024 का प्रश्नपत्र चोरी करने या उसके वितरण में शामिल था। जांच के दौरान वह फरार था और बाद में बिहार पुलिस ने उसे अन्य मामले में गिरफ्तार किया। नीट-यूजी मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने उसे हिरासत में लिया था।

एजेंसी ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसके खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। सीबीआई ने संजीव मुखिया को जानबूझकर बचाने या मामले से बाहर रखने के दावों को पूरी तरह तथ्यहीन बताया।

अमेरिका ने ईरान के बुशहर में की बमबारी

हूती ने सऊदी के दो तेल टैंकर किए तबाह, कुवैत में वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय

एजेंसी, तेहरान/वाशिंगटन

अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में हवाई हमला किया है। यह शहर ईरान का एकमात्र नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का घर है। अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हमले किए हैं। ईरान की सेना ने जवाब में अमेरिका के सहयोगी देशों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य की इस लड़ाई में अब यमन में सक्रिय ईरान समर्थक आतंकी समूह हूती खुलकर सामने आ गया है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम को बुशहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरीने बताया कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी तटीय शहर बुशहर पर हमला किया है। इससे जोरदार धमाका हुआ है। मौके पर आपातकालीन सेवाएं मौजूद हैं। बंदरगाह शहर बुशहर फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह शहर बुशहर प्रांत की राजधानी भी है। बुशहर की पहचान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वजह से होती है। यह ईरान का एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूस की मदद से निर्मित यह संयंत्र शहर के केंद्र से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर पूर्वी समय के अनुसार शाम 5:30 बजे ईरानी सैन्य ठिकानों पर और हमले शुरू किए गए हैं। यह हमले आम नागरिक जहाजों और कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए किया गया है। कुवैत की सेना ने कहा कि ईरान से होने वाले ड्रोन हमले को रोकने के लिए सारे देश में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया गया है। कुवैत सेना के जनरल स्टाफ ने कहा कि ड्रोन को मार गिराने पर धमाकों की आवाज आती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं।

ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ का कहना है कि अगर ईरान को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई तो इस क्षेत्र में स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता।

अमित शाह ने की असम के बाढ़ हालात की समीक्षा, 80 से अधिक लोग लापता

एजेंसी, गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा से बातचीत कर असम की बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। राज्य में बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

बातचीत के दौरान अमित शाह ने राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज या कल असम पहुंचेगा। विश्व सरमा लगातार दूसरे दिन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे। उन्होंने गोलाघाट जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और नुमलीगढ़ तथा गोलाघाट के कमारबंधा स्थित भास्कर सीनियर बेसिक स्कूल के राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की तथा राहत कार्यों की समीक्षा की।

रूस का दावा: यूक्रेन के ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाहों पर किए हमले

एजेंसी, मॉस्को

रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क में सैन्य उपयोग से जुड़े ठिकानों और जहाजों पर सटीक हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य आपूर्ति व्यवस्था को कमजोर करना था।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर माल उतार रहे एक मालवाहक जहाज, सैन्य सामग्री के भंडारण केंद्र तथा ईंधन और स्नेहक (फ्यूल एंड लुब्रिकेंट) भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय का दावा है कि इन ठिकानों का उपयोग यूक्रेनी सेना की रसद आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था। रूस ने यह भी कहा कि ओडेसा बंदरगाह पर माल लोडिंग और भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ दो मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाया गया, जिनके बारे में उसका दावा है कि वे यूक्रेनी सेना के लिए सामान लेकर पहुंचे थे।

इसके अलावा, रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी ड्रोन रखने वाले तीन गोदामों को भी क्षति पहुंचाने का दावा किया गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के साढ़े चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी काला सागर और आजोव सागर क्षेत्र दोनों देशों के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हाल के महीनों में दोनों पक्ष समुद्री मार्गों, बंदरगाहों और मालवाहक जहाजों पर हमलों को रणनीति तेज कर चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।